आज का विचार

जो जैसा
सोचता है
और करता है,
वह वैसा ही बन जाता है।

नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 7 | नोएडा, बुधवार, 7 अक्टूबर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

मप्र में दो बार आयोजित की जाएगी एमपीपीएससी की परीक्षा, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन की बड़ी घोषणा

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 06 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 में युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में प्रदेश के 20 हजार से अधिक युवा शामिल हुए। कॉन्क्लेव में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अवसरों की जानकारी दी गई और सीएम मोहन ने सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम मोहन ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम मोहन ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया कि अगले वर्ष से मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी।

सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 की बड़ी घोषणाएं

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी।
उच्च शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए शोधार्थियों मिलने वाली राशि 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह की जाएगी।
सभी शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कम्प्युटिंग लैब की स्थापना की जाएगी।
स्टार्टअप के लिए अच्छे आइडियाज मिलें, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का आइडिया फंड बनाने का प्रावधान किया गया है।
स्नातकोत्तर की छात्राओं को गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।
युवाओं के प्लेसमेंट कराने के लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी। सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए काम करेगी।
राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की 500 नई ईकाइयां बनाई जाएंगी।
शोध संस्था में 1 करोड़ रुपए का फंड विश्वविद्यालय निधि से स्थापित किया जाएगा।
प्रदेश के एक लाख युवाओं को कौशल उन्नयन योजना से जोड़ा जाएगा।
प्रत्येक संभाग में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2027 में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आयोजन होगा।

2026 का फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को मिला

अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमयी कणों को पकड़ने का तरीका खोजा

स्टॉकहोम (एजेंसी)। बेल्जियम में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हैल्जेन को 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार अंतरिक्ष से धरती तक आने वाले बेहद ताकतवर न्यूट्रिनो को पकड़ने और उनके बारे में पता लगाने में अहम काम के लिए दिया गया है। उन्होंने दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में न्यूट्रिनो पकड़ने वाली आइसक्यूब ऑब्जर्वेटरी बनाने का विचार दिया था।

फ्रांसिस हैल्जेन

नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाएगी। 2026 में नोबेल पुरस्कार की राशि करीब 11.5 करोड़ रुपए है। आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी दक्षिणी ध्रुव में है। इसके सेंसर दक्षिणी ध्रुव की करीब 1.5 से 2.5 किलोमीटर गहरी बर्फ के अंदर लगाए गए हैं।

अंतरिक्ष के न्यूट्रिनो पकड़ने के लिए बर्फ का इस्तेमाल– न्यूट्रिनो बहुत छोटे कण हैं, जो सूरज, तारों और अंतरिक्ष की बेहद ताकतवर घटनाओं से निकलते हैं। अरबों न्यूट्रिनो हर सेकंड हमारे शरीर और धरती के आर-पार निकल जाते हैं, लेकिन हमें उनका पता तक नहीं चलता।इन कणों की खास बात यह है कि वे अंतरिक्ष से निकलकर लगभग सीधी दिशा में धरती तक पहुंचते हैं और रास्ते में बहुत कम बदलते हैं। इसलिए अगर वैज्ञानिक इन्हें पकड़ लें, तो वे पता लगा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड में कहां और किस घटना से निकले थे। लेकिन न्यूट्रिनो को पकड़ना आसान नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

बीसीसीआई मीटिंग के बाद हरमनप्रीत ने छोड़ी कप्तानी

उनकी अगुआई में भारत ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीता; स्मृति बन सकती हैं अगली कप्तान

नईदिल्ली (एजेंसी)। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। यह फैसला एक दिन पहले गुवाहाटी में हुई

बीसीसीआई की मीटिंग के बाद आया है। बैठक में हरमनप्रीत, उपकप्तान स्मृति मंधाना और कोच अमोल मजूमदार शामिल हुए थे। टीम के भविष्य और कप्तानी को लेकर भी चर्चा हुई। हरमनप्रीत के बाद स्मृति मंधाना को अगला कप्तान बनाया जा सकता है।
37 साल की हरमनप्रीत के नाम कई रिकॉर्ड हैं। इनमें बतौर कप्तान भारत को पहला महिला वर्ल्ड कप जिताना शामिल है। उनकी कप्तानी में टीम ने 2012, 2016, 2022 और 2026 एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया। 2012 एशिया कप में हरमनप्रीत ने सिर्फ फाइनल में कप्तानी की थी। बाकी मैचों में मिताली राज ने टीम की कमान संभाली थी।

बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 6 सीटों पर वोटिंग

बंगाल में पुलिस ने हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया; ममता न सीएम-विधायक, न उम्मीदवार

नईदिल्ली (एजेंसी)। देश के चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग हुई।
इस दौरान आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी)

के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके पार्टी कार्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन पर चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनके बेटे गुलाम नबी आजाद भी रेजीनगर से उम्मीदवार हैं।
वहीं, मीडिया से बात करते हुए नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को जबरन उठाया जा रहा है।

27 के लिए 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत किया, पहली तिमाही के मजबूत आंकड़ों का फायदा मिला

वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने एफबाय 27 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.6 प्रतिशत बताया था। मंगलवार, 6 सितंबर को जारी लेटेस्ट रिपोर्ट 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में वर्ल्ड बैंक ने यह बात कही है।

ग्लोबल ट्रेड और दुनिया में तनाव के बावजूद भारत की इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत रही थी।

गांव-शहरों में मांग बड़ी, एक्सपोर्ट भी बड़ा– वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में निवेश और घरेलू खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

गांव और शहर दोनों में मांग– अच्छी खेती, सरकारी से किसानों को सिधी सहायता और सब्सिडी के चलते डिमांड बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर टैक्स में राहत और जीएसटी कटौती के बाद शहरी खपत में भी उछाल देखने को मिला है।

एक्सपोर्ट बड़ा

ग्लोबल लेवल पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट ने उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसे एफबाय 27 की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर माना जा रहा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन– सप्लाई साइड पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स की ग्रोथ पहली तिमाही में बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले साल 6.1 प्रतिशत थी।

कैबिनेट के दो बड़े फैसले

परिवहन और एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इन फैसलों में इंटेगरेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (आईटीएलए) की स्थापना और 10,000 करोड़ रुपये के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड (एसजीएफ) का गठन शामिल है। ये पहल देश के परिवहन और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों को नई दिशा देंगी। आईटीएलए का लक्ष्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करना है। यह परिवहन परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन और निगरानी में तालमेल बिठाएगा। आईटीएलए नीति अनुसंधान, परियोजना योजना व मूल्यांकन, निगरानी व समीक्षा, और डेटा विश्लेषण को एक साथ लाएगा।

स्कूलों में रोजाना संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिलेबस में पहले से ही शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई थी जिसके तहत स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान छात्रों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को इस पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ,

संदीप मेहता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि प्रस्तावना पहले से ही स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इसे छठी कक्षा से ही छात्रों को पढ़ाया जाता है।
संविधान की प्रस्तावना को राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग खारिज– दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और CBSE के स्कूली बच्चों में संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों के मार्च को पुलिस ने रोका

ज्ञानेश कुमार से मिलने पर अड़े राहुल गांधी, आकाशवाणी भवन में धरना

चुनाव आयुक्त हमसे क्यों नहीं मिल रहे

राहुल गांधी बोले- 300 सांसदों को रोका गया, पुलिस हमें धमका रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने विपक्षी सांसदों के संसद से चुनाव आयोग तक मार्च को बीच में ही रोके जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? पुलिस हमें चुनाव आयोग जाने से क्यों रोक रही है और धमका रही है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद से हमारे साथ 300 सांसद चुनाव आयोग जाना चाहते थे। हालांकि, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। हम करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिर 300 सांसदों को क्यों रोका गया है।

देश में क्या हो रहा– लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि करीब 300 सांसद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें यहीं रोक दिया। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें यहां क्यों रोका गया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है,

जबकि चुनाव आयोग का दफ्तर यहां से सिर्फ 50 मीटर दूर है। विपक्ष के 300 सांसद ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं, लेकिन वे डरे हुए हैं। देश में क्या हो रहा है? लोकतंत्र का क्या मतलब है अगर चुनाव आयोग चुने हुए प्रतिनिधियों से ही न मिले?

मैं यहां लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हूं– राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ भाजपा का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें खत्म कर देंगे। भाजपा क्या कहती है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है।

इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च में पहली बार दिखी बीजेपी की 'न्यूट्रल सहयोगी'

नई दिल्ली (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों के सांसदों ने मंगलवार को विरोध मार्च निकाला। जिसमें पहली बार बीजेपी की 'न्यूट्रल सहयोगी' मानी जाने वाली बीजेडी ने भी शिरकत की। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया। बीजेपी नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में बीजेडी सांसदों के मार्च में शामिल होने की जानकारी दी। संसद के मकर द्वार से निकला विपक्ष का मार्च नीति आयोग के पास ही रुक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी।

बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल

'हमारी मदद ज्ञानेश कुमार नहीं, गणेश जी कर रहे'

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस पार्टी देश में सरकार बदलने और किसी तरह राहुल गांधी को सत्ता में बिठाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए भारतीय लोकतंत्र और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर एक साथ हमला किया जा रहा है। यह प्रक्रिया कुछ महीने पहले शुरू नहीं हुई है बल्कि यह कई सालों से चल रही है। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने बार-बार किसी भी तरह से राहुल गांधी को लॉन्च और रिलॉन्च करने की कोशिश की है।

संबित बोले– हमारी मदद गणेश जी कर रहे– संबित पात्रा ने आगे कहा कि हमारी मदद ज्ञानेश कुमार नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद गणेश जी कर रहे हैं।

बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक के देवता गणेश जी हैं। देश की जनता के पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान है और जनता जानती है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोगों को वोट नहीं देना है। वोट उसको देना है जिसने कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा।

एसआईआर पर फैलाई जा रही फेक न्यूज– बीजेपी नेता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों सेएसआईआर को लेकर गलतफहमियां और फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका में मुख्य मांग थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए।

राहुल गांधी के झूठ का पुलिंदा खोलूंगा : पात्रा

संबित पात्रा ने कहा कि आज, मैं एक-एक करके राहुल गांधी के झूठ का पुलिंदा खोलूंगा। इस पूरे एक्स पोस्ट में, राहुल गांधी ने चार गुमराह करने वाले शब्दों इस्तेमाल किए हैं। पहला, 'फॉर्म 6 को गैरकानूनी तरीके से बदला गया है।' दूसरा, 'फॉर्म 6 को एकतरफा बदला गया।' तीसरा, 'इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहा है' और चौथा, 'इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भारतीय लोकतंत्र पर क्रिमिनल हमला।'

गुजरात में भीषण सड़क हादसा

तेज रफ्तार एसयूवी ट्रेलर ट्रक से टकराई, सात लोगों की दर्दनाक मौत

भावनगर (गुजरात)(एजेंसी)। गुजरात के भावनगर जिले में मंगलवार को उस समय चीखपुकार मच गई जब हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलसि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के भावनगर जिले में एक हाईवे पर खड़ी ट्रेलर ट्रक से एसयूवी के टकराने से सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने बताया कि पीड़ित भावनगर से अलंग जा रहे थे, जहाँ वे एक शिपयार्ड में काम करते थे। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10 बजे जिले के तलाजा तालुका में ट्रापाज गाँव के पास भावनगर-सोमनाथ नेशनल हाईवे के किनारे सर्विस रोड पर हुआ, जब तेज़ रफ़्तार एसयूवी खड़ी ट्रेलर से टकरा गई।

पुलिस पर भरोसा कायम हो ऐसे करें काम

पुलिस को पता होना चाहिए किन इलाकों में अपराध अधिक

नईदिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते यौन अपराधों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों से कहा कि पुलिस को पता होना चाहिए कि किन इलाकों में अपराध की दर अधिक है। इसके लिए नियमित सर्वेक्षण किए जाएं। स्थानीय लोगों से बातचीत की जाए। इससे उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है जो अपराध करने के बाद इन इलाकों में आकर रह रहे हैं।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ पार्क में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म व चलती स्लीपर बस में नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता लिज मैथ्यू को न्यायमित्र नियुक्त किया था और कई निर्देश जारी किए थे। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अब समय आ गया है कि संबंधित अधिकारी, दिल्ली पुलिस, चुनौती के अनुरूप काम करें ताकि लोगों का पुलिस पर भरोसा दोबारा कायम हो सके। पीठ ने पुलिस अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों से जमीनी स्तर पर काम करने को कहा। कहा कि केवल योजनाएं कागज पर तैयार कर देने से दुष्कर्म जैसे अपराधों को रोकना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। रोशनी और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने की बात कही। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पार्कों, रेलवे स्टेशनों, सबवे और ऐसे अन्य संवेदनशील स्थानों की पहचान की जानी चाहिए।

कोर्ट, सरकार, पुलिस को मिलकर करना होगा प्रयास

अदालत ने कहा कि न्यायपालिका, सरकार, पुलिस विभाग और न्यायमित्र को विभिन्न पहलुओं पर मिलकर विचार करना चाहिए और ऐसी घटनाओं को बार-बार होने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। अदालत ने कहा कि व्यवस्था में यदि कोई कमी है तो वह अपराध करने में सहायक नहीं बननी पीठ ने कहा, जब एक पार्क में नाबालिग के साथ कथित अपराध हुआ, तब स्थानीय लोगों ने पुलिस को असामाजिक तत्वों द्वारा पैदा की जा रही परेशानी की जानकारी दी थी।

एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री से 2.2 करोड़ के बेशकीमती पत्थर और कच्चे पन्ने बरामद, तस्कर गिरफ्तार

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2.02 करोड़ रुपये के बेशकीमती पत्थरों की तस्करी में एक यात्री को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बैंकॉक से आए इस यात्री को तीन अक्तूबर को हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया था। तलाशी के दौरान इसके पास से 1.01 करोड़ रुपये के 3,200 कीमती पत्थर और गहने मिले। इसके बाद आगे की जांच के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्री से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली। तलाशी में 196.67 किलो कच्चे पन्ने, 221 कैरेट कट और पॉलिश किए हुए रूबी और 45 कैरेट कट और पॉलिश किए हुए पन्ने बरामद हुए। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज और दूसरी चीजें भी मिलीं। जब्ती के पूरे सामान की कुल कीमत 2.02 करोड़ रुपये आंकी गई।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में खुला भारत का पहला कार्बन गार्डन, प्रदूषण से लड़ने में करेगा मदद

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरण के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम पहल की है। कॉलेज परिसर में सोमवार को 'कार्बन गार्डन' का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य वातावरण में कार्बन के अवशोषण को बढ़ाने के साथ जैव विविधता को बढ़ावा देना और प्रकृति आधारित समाधानों के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना है। गार्डन का उद्घाटन भारत के पहले कार्बन गार्डन के संस्थापक और दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख और रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के अध्यक्ष प्रो. दीनबंधु साहू ने किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव भारतीय संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रहा है। अब इस पारंपरिक जुड़ाव को आधुनिक विज्ञान और पर्यावरणीय समझ के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रो. साहू ने कहा कि दिल्ली जैसे शहरों में हरित क्षेत्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कार्बन गार्डन न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि छात्रों को प्रकृति से जोड़ने के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में भी मदद करेगा। उन्होंने युवाओं की पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया।

दिल्ली में एसआईआर में 10.28 लाख वोटर्स का दस्तावेजों से सत्यापन

नईदिल्ली, एजेंसी। एसआईआर के तहत नाम मैपिंग नहीं होने और तार्किक विसंगतियों से जुड़े 10,28,407 वोटर्स के मामलों का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जा चुका है। सीईओ कार्यालय के अनुसार इन वोटर्स से प्राप्त दस्तावेजों की जांच के बाद मामलों का निपटारा किया जा रहा है। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब दस्तावेज जमा कराने के लिए ईआरओ या एईआरओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बीएलओ संबंधित मतदाता के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ईसीआई नेट पर अपलोड करेंगे। इसके बाद ईआरओ दस्तावेजों के आधार पर मामले में निर्णय लेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में ही सुनवाई की जरूरत होगी। ऐसी सुनवाई भी ईआरओ के निर्णय के आधार पर प्राथमिकता के साथ आनलाइन कराने की व्यवस्था की गई है। एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है, जबकि नोटिस तथा दावे- आपत्तियों का निपटारा 30 नवबर तक किया जाएगा। एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब और फार्म जमा कराने के लिए 11 अक्टूबर को दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों पर फिर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वहीं, युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 7 और 8 अक्टूबर को दिल्ली के कालेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। एक अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा इन कैंप में फार्म- 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। चार अक्टूबर तक फार्म- 6 के 1,90,133 आवेदन मिले हैं। वहीं, 31 अगस्त से पहले प्राप्त 2,12,400 आवेदनों को जोड़ने पर अब तक फार्म-6 के कुल 4,02,533 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 31 अगस्त से चार अक्टूबर के बीच नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पश्चिमी जिले से 23,420 मिले हैं। इसके बाद उत्तर- पश्चिम से 20,165, दक्षिण-पूर्व से 18,831, पूर्व से 18,487, उत्तर-पूर्व से 17,831, दक्षिण- पश्चिम से 16,538 और दक्षिण जिले से 15,876 आवेदन आए है। वहीं, उत्तर से 14,273, आउटर नार्थ से 13,193, सेंट्रल नार्थ से 11,800, सेंट्रल से 8,470, ओल्ड दिल्ली से 7,988 और नई दिल्ली से 3,261 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी अवधि में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्म-7 के 5,020 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 के 69,817 आवेदन आए हैं। फार्म-6ए के तहत भी 356 आवेदन मिले हैं। 31 अगस्त से पहले मिले आवेदनों को जोड़ने पर अब तक फार्म-6ए के 1,707, फार्म-7 के 56,491 और फार्म-8 के 3,30,585 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह एसआइआर प्रक्रिया के दौरान नए नाम जोड़ने के साथ-साथ मौजूदा मतदाता सूची में सुधार और नाम हटाने के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन किए गए हैं।

पहले सड़क बनाओ, फिर जाम में फंसे वाहनों के लिए रास्ता खोजो

सात लेन का ट्रैफिक तीन लेन में सिमटा

नईदिल्ली, एजेंसी। मयूर विहार फेज-1 से आईएनए तक सिग्नल फ्री सफर के लिए तैयार किया गया बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज-दर-फेज की सरकारी प्लानिंग में उलझकर अब ट्रैफिक के बॉटलनेक में तब्दील हो गया है। अलग-अलग दिशाओं से आने वाला करीब सात लेन का ट्रैफिक आगे जाकर महज तीन लेन में सिमट रहा है। नतीजा यह कि जिस कॉरिडोर को तेज और निर्बाध आवाजाही के लिए बनाया गया था, वहीं वाहनों की रफ्तार थम रही है। सोमवार को इस उलझन से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस सिग्नल का सहारा लेती दिखी।

विशेषज्ञों के मुताबिक, अलग-अलग समय में दिल्ली की सरकारों ने बारापुला के फेज एक-एक कर पूरे तो कर दिए, लेकिन यह सवाल समग्र रूप से नहीं पूछा गया कि इन सभी फेज से निकलने वाला ट्रैफिक आखिर जाएगा कहां। फेज-3 खुलने के बाद वर्षों पुरानी प्लानिंग की यह खामी अब सड़क पर जाम के रूप में दिखाई दे रही है। एक तरफ मयूर विहार फेज-1 से तीन लेन का अतिरिक्त ट्रैफिक आ रहा है, दूसरी तरफ पहले से चल रहे कॉरिडोर का ट्रैफिक है और आगे जाकर क्षमता सीमित हो रही है।

बारापुला फेज-1 की योजना तैयार करने के समय से जुड़े एक वरिष्ठ अभियंता के मुताबिक, उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खेल गांव से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक खिलाड़ियों की सिग्नल फ्री आवाजाही सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य था। यूटीपैक में उस समय फेज-2 पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इसी जरूरत के हिसाब से फेज-1 में एक कैरिजवे को तीन लेन का बनाया गया। बाद में बारापुला में फेज-2 और फेज-3 जुड़ते गए।

अब समस्या यह है कि पहले से चल रहे कॉरिडोर में मयूर विहार फेज-1 से आने वाली तीन अतिरिक्त लेन का ट्रैफिक भी जुड़ रहा है। ऐसे में रिंग रोड के पास सन डायल से सिग्नल फ्री आवाजाही बनाए रखना चुनौती बन गया है।फेज-2 पर भी उस समय चर्चा हुई थी, लेकिन उसका विस्तृत स्वरूप सामने नहीं आया था। जून 2011 में पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति से मंजूरी मांगी।

पहले ढांचा तैयार हुआ, अब सवाल यह कि चलाएंगे कैसे

विशेषज्ञों का मानना है कि बारापुला की कहानी सरकार की कार्यशैली की दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। फेज-1 तैयार करते समय फेज-2 व फेज-3 का ध्यान नहीं था। तीनों अलग-अलग समय में तैयार हुई। अब पूरा तैयार होने के बाद ट्रैफिक को संभालने के तरीके तलाशने जा रहे हैं। मतलब यह कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसके बाद यह सवाल सामने आया कि उसे चलाएंगे कैसे। यूटीपैक के रिकॉर्ड के मुताबिक, 17 मार्च 2009 की बैठक में बारापुला नाले पर एलिवेटेड कॉरिडोर पर चर्चा हुई थी। इसके लिए कैबिनेट से करीब 550 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।

प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारों के लिए पहचान पत्र जरूरी, बरतनी होगी सावधानियां

नईदिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान मीडिया कवरेज और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन स्थलों पर काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह स्पष्ट करना है कि वे तनावपूर्ण स्थितियों के बीच पुलिस के कामकाज में बाधा डाले बिना अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां कैसे निभाएं।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों या धरना-स्थलों को कवर करने जाने वाले सभी मीडियाकर्मियों को अपने संबंधित संस्थान द्वारा जारी वैध पहचान पत्र हर समय अपने साथ रखना होगा। साथ ही, उन्हें यह कार्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की सलाह दी गई है, ताकि सुरक्षा बल ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को भीड़ के बीच पत्रकारों की पहचान करने में आसानी हो। इसके अलावा, पत्रकारों के पास वैध पीआईबी या डीआईपी मान्यता कार्ड होना भी बेहद मददगार बताया गया है। पुलिस के कामकाज में बाधा न डालने की हिदायत एडवाइजरी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि मीडियाकर्मी यह पूरी तरह सुनिश्चित करें कि उनकी मौजूदगी या कार्य-गतिविधियों के कारण पुलिस की कार्रवाई, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों या सुरक्षाकर्मियों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो।

सुरक्षित दूरी और स्पष्ट पहचान बनाए रखने की अपील

तनावपूर्ण और भीड़भाड़ वाली स्थितियों का जिक्र करते हुए पुलिस ने कहा है कि घटना स्थल पर मौजूद पत्रकारों को कवरेज और वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच उचित एवं सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें ऐसी जगहों पर खड़े होने की सलाह दी गई है।

डीयू कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा की मांग तेज

नईदिल्ली, एजेंसी। राजधानी में महिलाओं के खिलाफ आए दिन बढ़ते अपराधों के बीच अब कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठने लगी है।

छात्राओं को खुद की सुरक्षा करने के लिए आत्मरक्षा के गुर सिखाने के साथ ही कालेज परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की जा रही है। डीयू के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज (सीवीएस) की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) इकाई ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर छात्राओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाने की मांग की है। एबीवीपी की ओर से कॉलेज में दिल्ली पुलिस के सहयोग से नियमित आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कराने का सुझाव दिया गया है।

इसके साथ ही छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, आपात स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों और उपलब्ध हेल्पलाइन आदि की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की गई है। इसके अलावा कॉलेज परिसर में पिंक सेफ्टी बूथ स्थापित करने, परिसर और आसपास में लाइट लगाने, कॉलेज के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। छात्रसंघ की मांग है कि छात्राओं की शिकायतों व सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई हो। कॉलेज यूनिट अध्यक्ष मोहित वर्मा का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा केवल कालेज प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है पुलिस और समाज के सामूहिक प्रयास से ही सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सकता है।

एसीपी विवेक भगत को एडिशनल डीसीपी का चार्ज देने का फैसला टला, खुद की थी ये मांग

महिला पत्रकार उत्पीड़न मामला

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार ने सोमवार देर रात एक अहम कदम उठाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक भगत को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का 'करंट ड्यूटी चार्ज' सौंपने का निर्णय रोक दिया है। विवेक भगत पर हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है।

इससे पहले दिन के समय दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश में विवेक भगत समेत कुल 12 अधिकारियों को एडिशनल डीसीपी का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि, इस फैसले पर विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर स्पष्ट किया कि इन अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की यह प्रक्रिया गत 25 अगस्त को ही शुरू कर दी गई थी, जो कि हालिया घटनाओं से काफी पहले का मामला है। पांच अक्टूबर को आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद ही ये आदेश सामने आए थे।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि करंट ड्यूटी चार्ज देना केवल एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है, जिससे संबंधित अधिकारी को कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता है और न ही वे नियमित पद वाले अधिकारियों की सभी वैधानिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह पालन कर सकते हैं।

सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, आरोपी एसीपी विवेक भगत ने स्वयं यह अनुरोध किया है कि जब तक महिला पत्रकारों के कथित यौन उत्पीड़न मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती और वह संतोषजनक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, तब तक उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए। सरकार ने बताया है कि इसी अनुरोध के चलते पिछले आदेश में बदलाव किया जा रहा है और शेष 11 अधिकारियों को प्रभार सौंपने के संबंध में संशोधित आदेश फिर से जारी किया जाएगा।

दिल्ली में आपदा से निपटने के लिए सिविल डिफेंस वालंटियर्स के नए एनरोलमेंट शुरू, लंबे समय के बाद आए आवेदन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस वालंटियर्स के नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लंबे समय बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया से राजधानी में सिविल डिफेंस वालंटियर्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। नए वालंटियर्स को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, जनजागरूकता और मॉक ड्रिल जैसे कार्यों में लगाया जा सकेगा।

दिल्ली में सिविल डिफेंस वालंटियर्स लंबे समय से विभिन्न सरकारी अभियानों और आपात स्थिति में प्रशासन का सहयोग करते रहे हैं। यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा की स्थिति में राहत कार्य, प्राथमिक उपचार और लोगों को जागरूक करने में भी इनकी भूमिका रहती है। पूर्वी दिल्ली में फिलहाल करीब 550 वालंटियर्स हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर करीब एक हजार करने की जरूरत भी कुछ माह पहले दिल्ली विधानसभा में उठाई गई थी।

डिफेंस वालंटियर्स के कार्यों की सराहना की: पूर्वी दिल्ली के डीडीसी चेयरमैन एवं विधायक डॉ. अनिल गोयल द्वारा दिल्ली विधानसभा में सिविल डिफेंस वालंटियर्स के एनरोलमेंट का मुद्दा उठाया था। सरकार की ओर से दिल्ली में सिविल डिफेंस वालंटियर्स के नए एनरोलमेंट के लिए आमंत्रण शुरू किए गए हैं। इसे पूर्वी दिल्ली सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल डिफेंस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए डा गोयल ने सिविल डिफेंस वालंटियर्स के कार्यों की सराहना की थी। सिविल डिफेंस वालंटियर्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई बार विवाद भी सामने आए हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में वालंटियर्स को ड्यूटी पर लगाया गया था। बाद में ड्यूटी खत्म होने और भुगतान से जुड़े मुद्दों को लेकर वालंटियर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। कई वालंटियर्स ने लंबे समय तक ड्यूटी नहीं मिलने और मानदेय से जुड़े मामलों को लेकर अपनी आवाज उठाई थी।

पिंक कार्ड लेकर निकलीं महिलाएं, डीटीसी बसों में ईटीएम ने बढ़ाई मुश्किल; मशीन अटकी तो छूट गया स्टॉप

नईदिल्ली, एजेंसी। पिंक कार्ड हाथ में है और अगले स्टाप पर उतरना है, लेकिन ईटीएम मशीन अटक गई है। कंडक्टर भी मायूसी जताते हुए कहते है कि मशीन चलने तक इंतजार करना पड़ेगा। आईटीओ से शाहदरा जा रही कामकाजी महिला बुशरा खान के सामने सोमवार को यही सवाल खड़ा था कि निश्शुल्क यात्रा का अधिकार कार्ड से मिलेगा या मशीन के ठीक रहने पर। पिंक टिकट नहीं निकला तो चेकिंग में 200 रुपये जुर्माने का डर और मशीन चलने का इंतजार करें तो अपनी मंजिल छूटने का खतरा। डीटीसी बसों में पिंक कार्ड व्यवस्था लागू होने के पहले दिन की यह तस्वीर बयां कर रही थी कि नियम लागू करने की तैयारी और उसे जमीन पर उतारने की व्यवस्था के बीच अभी भी अंतर है। यह केवल बुशरा की ही परेशानी नहीं, बल्कि पहले दिन कई महिला यात्रियों की उलझन बनकर सामने आया। कार्ड होने के बावजूद ईटीएम अटकने पर यात्रा दर्ज कराने में दो से पांच मिनट तक लगे। अगले स्टाप पर उतरने वाली महिलाओं के लिए यह महज मशीन की तकनीकी दिक्कत नहीं थी। भीड़ के बीच हर बार मशीन के दोबारा चालू होने और कार्ड टैप होने का इंतजार करना पड़ा इसी तरह, कार्ड घर पर रह गया, अब पता चल रहा है कि इसके बिना निश्शुल्क यात्रा नहीं मिलेगी। मंडी हाउस से आनंद पर्वत जा रही सोनिया और मनीषा के पास पिंक कार्ड नहीं था। कार्ड बनवाया है, लेकिन तब इस्तेमाल नहीं हो रहा था। पहले दिन कंडक्टर ने नियम समझाकर दोनों को निश्शुल्क पास जारी कर दिया। मगर कुछ दूसरी बसों में कार्ड नहीं रखने वाली महिलाओं को किराया देना पड़ा। इससे पहले दिन ही यह सवाल खड़ा हो गया कि नियम एक है तो उसका पालन हर बस में एक जैसा क्यों नहीं दिखा? हमें पता ही नहीं था कि कार्ड आज से साथ रखना जरूरी है। एक महिला यात्री की यह बात बताती है कि समस्या तकनीक तक सीमित नहीं थी। पिंक कार्ड को लेकर यात्रियों में जानकारी का भी अभाव दिखा। कार्ड बनवाने की सूचना थी, लेकिन हर यात्रा में कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा, यह बात कई महिलाओं को बस में पहुंचने के बाद पता चली।

नोएडा में सड़क पर कुत्ता आने से अनियंत्रित बीएमडब्ल्यू डिवाइडर से टकराई, कारोबारी बाल-बाल बचे

एजेंसी

नोएडा। नोएडा के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदरपुर चौकी के सामने रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार के सामने अचानक आवारा कुत्ता आ जाने से कार अनियंत्रित हो गई और जोरदार रफ्तार में सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि लक्जरी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, हादसे के दौरान कार में लगे एयरबैग समय पर खुल गए, जिसकी वजह से गाड़ी चला रहे कारोबारी की जान बच गई और उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कारोबारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेक्टर-44 निवासी नितेश चौहान पेशे से कारोबारी हैं। रविवार देर रात करीब 12:15 बजे वे अपनी बीएमडब्ल्यू कार में सवार होकर आरके मॉल की दिशा से अपने घर सेक्टर-44 की ओर जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी सदरपुर चौकी के ठीक सामने पहुंची, तभी अचानक एक कुत्ता सड़क के बीचों-बीच आ गया। देर रात सड़क खाली होने और गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण कारोबारी ने कुत्ते को बचाने के लिए अचानक आपातकालीन ब्रेक लगाए और स्टीयरिंग मोड़ा। इसी प्रयास में कार से उनका नियंत्रण छूट गया और तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और सदरपुर चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत मौके की तरफ दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा बेहद डरावना था और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह कुचल गया था। गनीमत यह रही कि दुर्घटना के साथ ही बीएमडब्ल्यू कार के दोनों फ्रंट एयरबैग तुरंत खुल गए। सुरक्षा प्रणाली सही समय पर सक्रिय होने के कारण कारोबारी नितेश चौहान का सिर या छाती गाड़ी के डैशबोर्ड अथवा स्टीयरिंग से जोर से नहीं टकराई, जिससे बड़ा हादसा टल गया और उन्हें केवल हल्की खरोंचें व मामूली चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त कार से कारोबारी को बाहर निकाला और अपनी गाड़ी से पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका प्राथमिक उपचार किया और स्वास्थ्य जांच के बाद उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय लग्जरी कार में नितेश चौहान अकेले ही सवार थे और कोई अन्य यात्री गाड़ी में मौजूद नहीं था। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल की तस्वीरें और कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीएमडब्ल्यू कार का बोनट, बंपर और फ्रंट ग्रिल पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं तथा गाड़ी के दोनों एयरबैग फूले हुए बाहर लटके दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोग कार की मजबूती और एयरबैग तकनीक की तारीफ कर रहे हैं, जिसकी बदौलत इतने बड़े हादसे में भी चालक की जान सुरक्षित बच सकी। घटनास्थल पर तेज टक्कर के बाद बीच सड़क पर क्षतिग्रस्त कार खड़ी होने के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया था। देर रात का समय होने के कारण हालांकि बड़ा जाम तो नहीं लगा, लेकिन आने-जाने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बीएमडब्ल्यू कार को सड़क से हटवाकर किनारे करवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू हो सकी।

नूंह से निकलेगी भव्य सेवा ज्योति यात्रा, हजारों लोग

एजेंसी

नूंह,। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस तथा उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 7 अक्टूबर को नूंह में भव्य सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसी दिन गुरुग्राम में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद, जिला महामंत्री रमेश मानुवास तथा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष केशव पंडित सहित भाजपा नेताओं ने जिला उपायुक्त अखिल पिलानी, अतिरिक्त जिला उपायुक्त ज्योति और जिले के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यात्रा और जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। भाजपा नेताओं ने बताया कि 7 अक्टूबर को नूंह में भव्य सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के बाद पुलिस लाइन नूंह में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संबोधित करेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन तथा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा को लेकर कार्यकताओं में उत्साह है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकताओं और प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। चौधरी जाकिर हुसैन ने बताया कि 7 अक्टूबर को ही सेवा ज्योति यात्रा के तहत गुरुग्राम में भी समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे।

दाखिले का आखिरी मौका, खाली सीटों पर अब भी प्रवेश की उम्मीद

एजेंसी

गुरुग्राम। कॉलेजों में दाखिले के लिए चल रही लंबी प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। मंगलवार को दाखिले का आखिरी दिन है। ऐसे में सोमवार को जिले के राजकीय कॉलेजों में अंतिम चरण की भौतिक काउंसलिंग शुरू हुई। रिक्त सीटों की जानकारी लेने और दाखिले का अवसर पाने के लिए विद्यार्थी कॉलेजों में पहुंचे। कई चरण की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कुछ पाठ्यक्रमों में सीटें खाली हैं। इन्हीं सीटों को अंतिम दो दिनों में भरने की कवायद की जा रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से छह अक्टूबर तक दाखिले की अनुमति दी गई है। सोमवार को विद्यार्थियों को उपलब्ध सीटों और पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र विद्यार्थियों को रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया गया। मंगलवार को भी कॉलेजों में भौतिक काउंसलिंग के माध्यम से दाखिले होंगे। इसके बाद इस सत्र में नियमित दाखिले की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अंतिम दिन का इंतजार नहीं कर रहे विद्यार्थी सोमवार को कुछ कॉलेजों में विद्यार्थी सुबह से ही पहुंचने लगे। इनमें ऐसे विद्यार्थी भी शामिल रहे, जिन्होंने पहले आवेदन किया था, लेकिन सीट आवंटित नहीं हो सकी थी। कुछ विद्यार्थी अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में सीट खाली होने की जानकारी लेने पहुंचे। कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के अनुसार विद्यार्थियों को विकल्प बताए गए और दस्तावेज पूरे कराने की प्रक्रिया की गई। कॉलेज प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे मंगलवार को अंतिम समय का इंतजार न करें। रिक्त सीटों की स्थिति सेक्टर-9 स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर करीब 1250 सीटों में से लगभग 200 सीटें अभी खाली हैं। वहीं स्नातकोत्तर स्तर पर करीब 200 सीटों पर दाखिला होना बाकी है। इन सीटों को भरने के लिए अंतिम चरण में विद्यार्थियों को अवसर दिया जा रहा है। सोमवार को भी विद्यार्थी रिक्त सीटों और उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी लेने पहुंचे। द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय में कुल 3120 सीटों में से करीब 2900 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। यहां कुछ सीटें विशेष रूप से बीएससी के पाठ्यक्रमों में खाली हैं। अन्य अधिकांश पाठ्यक्रमों में दाखिले लगभग पूरे हो चुके हैं। अंतिम चरण में इन रिक्त सीटों को भरने के लिए विद्यार्थियों को भौतिक काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है।

सफाई निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, संसाधनों की होगी जांच

एजेंसी

गुरुग्राम । शहर की सफाई व्यवस्था को पारदर्शी और दुरस्त बनाने के लिए निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने सलाहकार बीर सिंह छौक्कर को स्वच्छता निगरानी सेल का नया नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी अब शहर में सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों और संसाधनों की जांच करेंगे। इसको लेकर अतिरिक्त निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि शहर में सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। निगम द्वारा करोड़ों रुपयों के टेंडर लगाकर निजी एजेंसियों को सौंप दिए हैं, लेकिन धरातल पर एजेंसी कितने संसाधनों और मैनपावर कितनी लगा रहे हैं इसकी निगरानी निगम द्वारा नहीं की जा रही है। यहीं कारण है कि शहर में करोड़ों खर्च तो कर रहा है,लेकिन धरातल पर काम हो रहा है या नहीं इसकी जांच के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है। अतिरिक्त आयुक्त-1 अंकिता चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बीर सिंह छौक्कर शहर में कचरा उठाने वाले वाहनों के संचालन और उनकी आवाजाही पर सीधी नजर रखेंगे। इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों और वाहन चालकों की उपस्थिति (हाजिरी) और दैनिक कामकाज की भी औचक जांच की जाएगी। घरों से कूड़ा उठाने वाली निजी एजेंसियों के संसाधनों की कार्यप्रणाली की भी कड़ी समीक्षा होगी।

मानेसर में 24.40 करोड़ रुपये से बनेंगे खेल स्टेडियम और बहुउद्देशीय भवन

एजेंसी

गुरुग्राम । मानेसर क्षेत्र के निवासियों और युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। मानेसर नगर निगम ने क्षेत्र में खेल, मनोरंजन और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तीन बड़े विकास प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। इन परियोजनाओं पर कुल 24 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। निगम के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं विकसित होने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि मानेसर नगर निगम का गठन हुए करीब छह साल हो गए हैं। मानेसर निगम क्षेत्र में अधिकत ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। गांव में शहर की तर्ज पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। निगम द्वारा ग्रामीण आंचल में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इनडोर और ओपन स्पॉर्टस कॉम्पलेक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसको लेकर प्रत्ये गांव में कहीं स्टेडियम तो कहीं पर सामुदायिक भवन जैसी सुविधांए गांव में देने की योजना बनाई है। परियोजनाओं के तहत सबसे बड़ा निवेश हरसरू गांव के वार्ड नंबर-2 में किया जा रहा है। यहां मल्टीपर्पज (बहुउद्देशीय) बिल्डिंग के निर्माण के लिए नौ करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस भवन के बन जाने से स्थानीय लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक बेहतरीन स्थान मिल सकेगा। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में रिक्रिएशन और इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस इंडोर स्टेडियम के बनने से स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को मौसम की मार से राहत मिलेगी और वे सालभर इनडोर खेल गतिविधियों का लाभ उठा सकेंगे। गढ़ी गांव में खुलेगा ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समानेसर के गढ़ी गांव में चंदू रोड के पास एक भव्य ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर नौ करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस खेल परिसर के बनने से युवाओं को खेलकूद के लिए खुला और आधुनिक मैदान मिलेगा, वहीं सामुदायिक भवन के माध्यम से सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन आसानी से हो सकेगा। विकास कार्यों को मिलेगी नई गति नगर निगम के इन तीनों प्रस्तावों (हरसरू और गढ़ी की परियोजनाओं) को जोड़ने पर कुल बजट 24 करोड़ 40 लाख रुपये बैठता है। जानकारों का मानना ह

15 अक्टूबर तक होंगे 30 खेलों के ट्रायल, महाकुंभ के लिए चुने जाएंगे खिलाड़ी

एजेंसी

गुरुग्राम। महीनों से प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे गुरुग्राम के खिलाड़ियों के लिए अब मैदान में उतरकर प्रतिभा दिखाने का मौका आ गया है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2026-27 के लिए जिला स्तर पर खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम समेत प्रदेश के सभी जिलों में 30 खेलों के ट्रायल 15 अक्टूबर तक पूरे कराने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार चयन प्रक्रिया केवल मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रायल की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इससे चयन प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड तैयार रहेगा और बाद में किसी तरह की शिकायत होने पर प्रक्रिया की जांच भी की जा सकेगी। खेल विभाग ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ट्रायल के आयोजन से जुड़े कई निर्देश जारी किए हैं। संबंधित खेल के ट्रायल की जानकारी कम से कम सात दिन पहले प्रकाशित करानी होगी, ताकि इच्छुक खिलाड़ियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके। ट्रायल मंडलीय उपनिदेशक, जिला खेल अधिकारी और संबंधित विभागीय प्रशिक्षक की निगरानी में कराए जाएंगे। निजी खेल नर्सरी के प्रशिक्षकों की ओर से लिए गए ट्रायल को मान्य नहीं माना जाएगा। किसी खेल में गुरुग्राम में विभागीय प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नजदीकी जिले से प्रशिक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। यदि वहां भी संबंधित खेल का प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है तो मुख्यालय स्तर से तकनीकी अधिकारियों की सूची के आधार पर विशेषज्ञ उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि किसी खेल में प्रशिक्षक की कमी के कारण खिलाड़ियों का चयन प्रभावित न हो। प्रदेश के दूसरे जिलों में जारी ट्रायल कार्यक्रमों में खिलाड़ियों के लिए पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। खिलाड़ियों से फोटो, आधार कार्ड और रिहायशी प्रमाण पत्र मांगा गया है। वहीं किसी दूसरे जिले का निवासी खिलाड़ी यदि संबंधित जिले में पढ़ाई कर रहा है तो स्कूल या कॉलेज का पहचान पत्र और संस्थान का प्रमाण पत्र दिखाकर ट्रायल में शामिल होने की व्यवस्था भी रखी गई है। गुरुग्राम में भी ट्रायल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को पात्रता और दस्तावेज संबंधी जानकारी पहले संबंधित प्रशिक्षक से लेने की सलाह दी जाएगी। कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो जैसे भार वर्ग वाले खेलों में खिलाड़ियों के वजन को भी चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जारी कार्यक्रम के अनुसार ऐसे खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर वजन कराने के लिए पहुंचना होगा और तय समय के बाद वजन की अनुमति नहीं होगी। इससे वजन वर्ग के आधार पर होने वाले चयन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। महाकुंभ के जिला स्तर के चयन में ताइक्वांडो, क्रिकेट, खो-खो, कुश्ती, तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, जूडो, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, टेनिस समेत करीब 30 खेल शामिल हैं। अलग-अलग खेलों में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों की टीम तैयार होगी, जो आगे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी अवधि में अलग-अलग खेलों के ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में खेल महाकुंभ के कार्यक्रम को लेकर खिलाड़ियों को लंबे समय से इंतजार था।

संक्षिप्त डायरी

अतिथि अध्यापकों का प्रदर्शन, डीसी कार्यालय घेरा

एजेंसी

गुरुग्राम । अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की नीति को लेकर सोमवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। शिक्षा विभाग में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पहुंचे अतिथि अध्यापकों ने जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर तीन साल की नीति के तहत उन्हें नियमित करने की मांग की।राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के जिला प्रधान सुनील कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अतिथि अध्यापक उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार यदि 10 साल की नीति के तहत उन्हें नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो वे इसका विरोध करेंगे। अतिथि अध्यापकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चेतावनी देते हुए कहा कि तीन साल की नीति को लागू नहीं किया गया तो 10 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। महिला अतिथि अध्यापकों ने कहा कि वे अपना सामान लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। अतिथि अध्यापकों का कहना है कि सरकार जिस तीन साल की नीति को नजरअंदाज कर रही है, उसे लेकर न्यायालय से भी पहले मंजूरी मिल चुकी है। उनका दावा है कि इस नीति के तहत नियमित होने से लंबे समय से सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को लाभ मिलेगा। वहीं, उनका आरोप है कि सरकार दस साल की नीति के तहत नियमित करने की तैयारी कर रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं।

बाजरे का पंजीकरण सही न होने से चिंता

एजेंसी

सोहना । बाजरे की बिक्री के दौरान किसानों का फसल पंजीकरण सही नहीं किए जाने से परेशानी बढ़ गई है। किसान फसल का सर्वे करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे। इससे किसानों को हजारों रुपये का घाटा हो रहा है। स्थानीय अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। बीते चार दिन में 13 किसानों द्वारा करीब 300 क्विंटल बाजरा बेचा गया है। सोमवार को फसल बिक्री का पांचवा दिन है। दोपहर तक करीब 15 किसान सैंकड़ों क्विंटल बाजरे को लेकर मंड़ी पहुंचे थे। हरियाहेड़ा निवासी किसान देशराज ने बताया कि छह एकड़ में बाजरे की फसल उगाई, लेकिन मात्र आठ क्विंटल ही बाजरे का पंजीकरण हुआ है। वह बाकी बाजरे को औने-पौने भाव में बेचने के लिए मजबूर है। अभयपुर निवासी जगती खटाना ने बताया कि उसकी फसल का भी मात्र आठ क्विंटल का पंजीकरण किया है। वह केवल आठ क्विंटल बाजरे को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। फसल का सर्वे करने का काम राजस्व विभाग का है। इसकी जानकारी किसान को ब्लॉक पटवारी ही बता सकते हैं। इसलिए किसान फसल पंजीकरण को लेकर अपने हल्का पटवारी से संपर्क करें। -राजेन्द्र सिंह, मार्केट कमेटी सचिव, सोहना पटवारियों ने मौके पर जाकर सर्वे करने के बाद ही फसल का पंजीकरण किया है। घंघौला में खेतों के अंदर पानी जमा होने तथा हरियाहेड़ा-अलीपुर में नेटवर्क कम होने के कारण फसल का पंजीकरण करने में परेशानी हुई है। पटवारियों द्वारा 90 फीसदी फसल का सर्वे पूरा कर लिया है।

ढाई हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू

एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अमीनाबाद, पतवाड़ी और बिसरख समेत 17 गांवों में रोशनी से अछूती गलियां भी जल्दी एलईडी स्ट्रीट लाइट से जगमग होंगी। प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने दीवाली को देखते हुए लाइट लगाने का काम तेज कर दिया है। ढाई हजार से अधिक नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। अधिकारी के मुताबिक सूरजपुर, भोला रावल, तिलपता करनवास, कुलेसरा, कैलाशपुर उर्फ किराचपुर, बिसरख, ऐमनाबाद, सादोपुर, इटेड़ा, खोदना खुर्द, खैरपुर गुर्जर, छपरौला, खेड़ा धर्मपुरा, मिलकलच्छी, खेड़ी, भनौता और सुनपुरा गांव में 2500 से अधिक नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इन गांवों में आबादी का विस्तार होने से कई गलियों में अंधेरा रहता है। इससे रात के समय हादसे की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र के लोगों द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सीईओ रवि कुमार एनजी के निर्देश पर अंधेरे वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां पर लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस पर 3.34 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वरिष्ठ प्रबंधक अजीत भाई पटेल ने बताया कि बिसरख, अमीनाबाद और पतवाड़ी में दीवाली से पहले काम पूरा कर लिया जाएगा। सभी 17 गांवों में अगले 5 से 6 माह में काम पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक इन गांवों में पूर्व में कराए गए काम के दौरान कुछ हिस्सों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शेष रह गया था। दरअसल, बिजली की बचत के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के तहत शहर के सेक्टरों और अधिसूचित क्षेत्र के गांवों में सोडियम लाइट को हटाकर उनके स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइटे लगाने का फैसला लिया था। इसके तहत अब तक एक लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 17 गांवों में अंधेरे वाले स्थानों पर एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।

पड़ोसी पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप

एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। ऐच्छर गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने पड़ोसी और उसके परिवार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक होरेश ने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने ऐच्छर में एक भूखंड खरीदा था। पड़ोसी जसराज और उसके परिवार के लोग उनसे रंजिश मानते हैं। आरोप है कि इसी के चलते शनिवार को जसराज और उसके परिवार ने पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ित और उनके माता-पिता को बुरी तरह पीटा। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। मारपीट में पीड़ित और उसके माता-पिता को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि आरोपी जसराज, मोहित, पवन और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

तृष्णा की आग में जलता मनुष्य

मनुष्य के जीवन में इच्छाओं का होना स्वाभाविक है। इच्छाएं उसे आगे बढ़ने, परिश्रम करने और नई उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन जब इच्छा आवश्यकता की सीमा पार कर तृष्णा बन जाती है, तब वही मनुष्य के लिए अशांति का कारण बन जाती है। तृष्णा ऐसी भूख है जिसे जितना खिलाया जाए, वह उतनी ही बढ़ती जाती है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता और संग्रह की चाह जब जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाती है, तब व्यक्ति के पास बहुत कुछ होते हुए भी भीतर से खाली रह जाता है।

सूफी संत जुन्नैद से जुड़ा प्रसंग इसी सत्य को सरल ढंग से समझाता है। एक व्यक्ति उनके पास पांच सौ स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचा और कहा कि उसके

अनीता यादव

पास सब कुछ है, फिर भी वह संसार की पूरी संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। संत ने उसकी भेंट लौटा दी और समझाया कि संपत्ति का अभाव उतना बड़ा दुख नहीं है, जितना संतोष का अभाव। जिसके भीतर संतोष नहीं है, उसे कितना भी धन मिल जाए, उसकी इच्छा समाप्त नहीं होगी। यह बात केवल धन के संदर्भ में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह उपलब्ध चीजों का आनंद लेने के बजाय उन चीजों के पीछे भागता रहता है, जो उसके पास नहीं हैं। एक व्यक्ति के पास घर है तो वह बड़ा घर चाहता है, बड़ा घर मिल गया तो उससे अधिक महंगा घर चाहता है। धन बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। उपलब्धि मिलती है तो उससे बड़ी उपलब्धि की चिंता शुरू हो जाती है। इस दौड़ का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। परिणाम यह होता है कि साधन बढ़ते जाते हैं, लेकिन मन की शांति घटती जाती है। तृष्णा का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और लालसाओं के बीच अंतर करना भूल जाता है। आवश्यकता पूरी होने के बाद भी मन बार-बार कहता है कि थोड़ा और चाहिए। यही 'और' धीरे-धीरे जीवन पर अधिकार कर लेता है। व्यक्ति वर्तमान को भूलकर भविष्य के संग्रह में लगा रहता है। उसके पास समय नहीं होता कि वह अपने भीतर झांक सके और यह पूछ सके कि वास्तव में उसे चाहिए क्या। तृष्णा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है। इसका प्रभाव परिवार, समाज और राष्ट्र के जीवन पर भी पड़ता है। जब संग्रह की भावना बढ़ती है तो दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा होने लगती है। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रयास के बजाय लालच में बदल सकती है। सामाजिक जीवन में दिखावा बढ़ता है और व्यक्ति अपने मूल्यांकन का आधार भी दूसरों की संपत्ति और प्रतिष्ठा को बना लेता है। इससे असंतोष, ईर्ष्या और तनाव को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भी तृष्णा के प्रभाव को समझना आवश्यक है। सत्ता स्वयं में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक माध्यम है, लेकिन सत्ता को साधन के बजाय निजी स्वार्थ या निरंतर प्रभुत्व की वस्तु मान लिया जाए तो उसके उद्देश्य पर प्रश्न खड़े होते हैं। इसी तरह राजनीति में पद, प्रभाव, प्रतिष्ठा और संसाधनों की असीम चाह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए राजनीतिक जीवन में भी पारदर्शिता, जवाबदेही, सेवा भावना और मर्यादा का महत्व बना रहता है। किसी एक दल या व्यक्ति तक बात सीमित नहीं है; तृष्णा का प्रश्न व्यापक मानवीय प्रवृत्ति से जुड़ा है। सामाजिक क्षेत्र में भी यही स्थिति दिखाई देती है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और चरित्र निर्माण के बजाय केवल ऊंची आय प्राप्त करना बन जाए, व्यवसाय का उद्देश्य समाज की आवश्यकता पूरी करने के बजाय अधिकतम संग्रह रह जाए और प्रतिष्ठा का आधार सेवा के बजाय प्रदर्शन बन जाए, तो विकास का अर्थ अधूरा हो जाता है। बाहरी समृद्धि के साथ आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। तृष्णा को समझाने वाला एक सुंदर दृष्टांत है जिसमें एक संत एक सेठ को एक भूखी स्त्री के माध्यम से तृष्णा का स्वरूप समझाते हैं। वह स्त्री जितना भोजन करती है, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। अंत में संत बताते हैं कि वह स्त्री वास्तव में तृष्णा है। यह दृष्टांत बताता है कि तृष्णा की भूख बाहरी वस्तुओं से शांत नहीं होती। उसे संतोष ही शांत कर सकता है। भारतीय चिंतन परंपरा ने इसलिए संतोष को बहुत महत्वपूर्ण माना है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे या प्रगति की इच्छा त्याग दे। संतोष का अर्थ है कि उपलब्ध साधनों के प्रति कृतज्ञ रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और अनावश्यक लालसा को नियंत्रित करना।

राजनैतिक व्यंग्य : आशीर्वाद का दीया!

-संजय पराते-

दिवाली आने में अभी पौने दो माह बाकी है, लेकिन इसके पहले ही पूरे देश को जगमगाने की प्लानिंग बन चुकी है। मोदीजी ने अपना जन्म दिन 17 सितंबर को बताया है, तो बिलकुल मानिए कि हिंदू राष्ट्र की इस पावन धरा पर वे 17 सितंबर को ही अवतरित हुए होंगे। जिन्हें शक हो, वे मोदीजी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की मार्कशीट में लिखी जन्म तिथि देख सकते हैं। जिन्हें यह न मिलें, वे एप्स्टीन फाइल खोलकर देख सकते हैं। वहां मोदीजी की जन्म कुंडली में उनका अवतरण दिवस 17 सितंबर दर्ज ही होगा।

मोदीजी के अवतरण दिवस को यादगार बनाने के लिए संघी गिरोह क्या कुछ नहीं कर रहा है! भाजपा सरकारें फरमान जारी कर रही है कि तैयारी ऐसी हो कि तेल और दीयों की कोई कमी न हो। खाड़ी के तेल की कमी के साथ हमारे तेल मिलों में भी तेल का उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि तिलहन की पैदावार घट रही है। तो भी कोई बात नहीं, देश का तेल निचोड़ों, तेल मिलें बंद नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ जनता को निचोड़ोगे, तो देश क्या, दुनिया में भी तेल की कमी नहीं होगी। इतना तेल निकलेगा कि होली में भी जलाने के काम आएगा। 17 सितंबर से होली तक तेल जलाओ उत्सव मनाया जा सकता है।

तो मित्रों, अब आप लोग मान ही लो कि इस धरा पर 17 सितम्बर को ही मोदीजी का अवतरण हुआ था। भारत वर्ष नाम के धरा के इस हिस्से को ही यह सौभाग्य प्राप्त होना था। विज्ञान कथाएं बताती हैं कि जिस तरह इस मिट्टी में राम अवतरित हुए थे रावण से मुक्ति दिलाने के लिए, कृष्ण अवतरित हुए थे कंस मामा से मुक्ति दिलाने के लिए, उसी तरह मोदीजी भी अवतरित हुए हैं भारत की इस पावन धरा को म्लेच्छों और नाराज फूफाओं से मुक्ति दिलाकर हिंदू राज लाने के लिए। म्लेच्छों के खिलाफ 2002 में गुजरात में वे एक धर्म युद्ध लड़ चुके है। यह धर्म युद्ध इतना भीषण था कि वे राज धर्म भी भूल गए। अटल बिहारी के याद दिलाने से भी उन्होंने इसे याद करने से मना कर दिया था। याद रखा, तो केवल अर्जुन की तरह उस चिड़िया की आंख को, जिसे निशाना बनाना था। मोदीजी हिंदू हृदय सम्राट ऐसे ही नहीं कहलाते। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अपने तप के बल पर वे अब पूरे देश को मुसलमानों और इस्लाम से मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। राम और कृष्ण को उन्होंने इस अभियान के लिए अपने रथ में जोत दिया है।

तभी तो वे अवतार पुरुष हैं, इसलिए उनका अवतरण ही होना था। साधारण मनुष्य तो जन्म ही लेते हैं। अधिकांश को रोज की खट-खट में अपनी जन्म तिथि भी याद नहीं रहती, जन्म दिन मनाने की बात तो दूर ही रही। जो नॉन-बायोलॉजिकल होते है, वे जन्म लेकर भी अवतरित होते हैं। कलयुग के अवतारी पुरूष का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि पूरी दुनिया से कहे कि उसके लिए आशीर्वाद का दीया जलाओ, उसके शतायु पार होने और आजीवन सत्ता सुख भोगने की कामना करो।

यह देश का सौभाग्य है कि उसे ऐसा प्रतापी नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मिला। प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी बाजपेयी आदि-इत्यादि भी थे, लेकिन वे सभी बायोलॉजिकल थे। 2047 के बाद राहुल गांधी भी यदि कभी पीएम बन पाएं, तो भी वे रहेंगे बायोलॉजिकल ही। फिर ये सब क्या खाकर मोदीजी का मुकाबला करेंगे! मोदीजी ने दिखा दिया है कि नेहरू का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाता है। नेहरू का विकास पिछड़ा हुआ था, बायोलॉजिकल जो थे। मोदीजी का विकास आधुनिक है, नॉन-बायोलॉजिकल जो ठहरे। गम तो केवल इतना है कि मोदीजी इतनी देरी से क्यों अवतरित हुए? आजादी से पहले ही हो जाते, बाल-काल से ही प्रधानमंत्री बन जाते, तो आज देश कितना आगे बढ़ जाता! लेकिन क्या करें, मोदीजी से पहले पैदा होकर नेहरू देश के विकास के लिए बाधक बन गए। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, नेहरू के किए-धराये पर पानी फेरकर मोदीजी देश का विकास कर रहे हैं। रात के अंधेरे में नेहरू चुपके से देश को पीछे खींच देते हैं, कभी-कभी तो लंगड़ी मारकर गिरा देते हैं। दिन में फिर धक्का मारकर मोदीजी देश को आगे बढ़ा देते हैं। पिछले 12 सालों से यही खेल चल रहा है। यकीन मानिए, लड़ाई नेहरू और मोदीजी में नहीं है। यह लड़ाई तो अंधेरे और जगमगाते दीयों के प्रकाश की, बायोलॉजिकल पीएम और नॉन-बायोलॉजिकल अवतार के बीच में है। ये देश पराक्रमी अवतारों का देश है। अवतारवाद यहां की प्रजा की रग-रग में बसा है। फिर मोदीजी के मुकाबले नेहरू कहां टिकेंगे?

लेकिन नामुराद जनता को फिर भी समय नहीं मिला। इस दिन भी वह अपनी रोज की खट-खट में ही खट रही थी। वो तो भला हो, हमारे कलेक्टरों का, डिप्टी कलेक्टरों का, अलाने और फलाने अधिकारियों का कि दौड़ती गाड़ियों, पैदल चलते राहगीरों को रोककर सड़कों पर दीपमालाएं सजा दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की गौरव पथ पर जगमगाते दीपों को निहारते अखबारों में तस्वीर छपी है। समाचार छपा है कि राजधानी रायपुर में ही 25 लाख दीये जलाए गए। इस हिसाब से पूरे देश में इतने दीये तो जल ही गए होंगे, जितनी इस पृथ्वी की आबादी नहीं है। और वह भी, सड़कों पर और मंदिरों में ही, सरकारी खर्चे से। सरकारी पैसा भी जनता का ही पैसा होता है, जिसे खर्चने के लिए जनता की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और न ही बजट में आबंटन की। जब इतने दीये जले हैं, तो यह तो माना ही जा सकता है कि इसकी रोशनी गरीब की उस झोपड़ी तक भी जरूर पहुंची होगी, जिसकी औकात अब ढीबरी जलाने की भी नहीं बची है। क्यों नहीं बची है, इसका पता कुछ दिनों के बाद तब चलेगा, जब यह सामने आएगा कि इन दीयों और इसमें डालने वाले तेल को संघी सरकार ने किस भाव से खरीदा था। मोदीजी के अवतरित होने की खुशी में पूरे देश में खरबों के वारे-न्यारे न हो, तो ऐसे अवतरण का भी क्या मतलब! क्या मोदीजी अडानी और अंबानीजी के ही बने रहेंगे!!

वैसे इस दिन को चिर-स्थायी, शाश्वत और सनातनी बनाने के लिए संघी गिरोह और भी बहुत कुछ कर सकता है। करना भी चाहिए। वैसे भी मोदीजी राम और कृष्ण से बड़े अवतारी पुरुष हैं। जो रामजी पिछले 500 सालों से बेघर थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने का काम मोदीजी ने ही किया है, किसी और पार्टी और नेता में कहां इतना दम था! आवास भी इतना बड़ा कि प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ भी शरमा जाएं। रामजी की उंगली पकड़कर मोदीजी ने उन्हें इस आवास में स्थापित किया है। यह अलग बात है कि रामजी की सेवा करने की जिम्मेदारी जिन चौकीदारों को सौंपी थी, वे ही चोर निकले। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। यह कहावत तो सबने सुनी है कि सेवा करोगे, तो मेवा मिलेगा।

तो भाईयों-बहनों, रामजी की सेवा मोदीजी और उनके लगे-भगे करेंगे और बदले में रामजी उन्हें सत्ता में बैठाए रहेंगे, कम से कम 2047 तक तो अवश्य ही। रामजी ने भी कह दिया है, मैं तो त्रेता युग का राजा था, कलयुग के राजा तो ये मोदीजी ही है, जिन्होंने मुझ बेघर को घर दिया! मोदीजी इस धरा पर अवतरित न हुए होते, तो पता नहीं, मुझे और कितनी सदियों तक बेघर भटकना पड़ता!! रामजी की इस घोषणा पर स्वर्ग में मोदीजी के जयकारे लगने लगे, जिसकी आवाज इस मर्त्य लोक में अभी तक गूंज रही है।

अब जब रामजी से बड़े अवतारी पुरुष मोदीजी बन ही गए हैं, तो मोदीजी के अवतरण दिवस को चिर स्थायी बनाने के लिए थोड़ा-सा इतिहास भी बदला जा सकता है। रामजी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि उनकी दिवाली को हर साल 17 सितम्बर को ही मनाने की घोषणा कर दी जाएं। बस एक सरकारी आदेश निकालने भर की जरूरत है। सरकारी फरमान में 'आदेशानुसार रामजी' लिखने से ही काम चल जाएगा।इससे जनता भी 17 सितम्बर को दीया जलाने के लिए मजबूर हो जाएगी। दिवाली के दिन तो वैसे भी गरीब से गरीब आदमी भी अपने पकाने की कड़ाही से एक छंटाक तेल बचाकर दीया तो जलाता ही है, दरवाजा भी खोलकर टिमटिमाती रोशनी में बैठे रहता है कि कब लक्ष्मीजी घर में घुसे और वह उसे बंधक बनाकर अपनी गुदड़ी में लपेट लें। लेकिन लक्ष्मीजी भी कम चालाक नहीं है। वह ऐसे गरीबों को घास भी नहीं डालती, उनके मोहल्लों से गुजरना तो दूर की बात है। वह अपने उल्लू पर सवार होकर सीधे मोदीजी से मिलती है और अडानी-अंबानी की तिजोरी में घुस जाती है। यह तिजोरी भी इतनी बड़ी और आलीशान है कि देखती है कि स्वर्ग के सभी देवता तो यही आराम फरमा रहे हैं। फिर तो देवीजी का भी यहां से कहीं और कूच करने का मन ही नहीं करता।

17 सितम्बर को रामजी की दिवाली और मोदीजी का अवतरण दिवस, दो अवतारों का ऐतिहासिक संगम दिवस होगा यह। पूरी दुनिया देखेगी कि इधर रामजी मोदीजी के नाम के दीये जलवा रहे हैं और उधर मोदीजी विपक्ष का दिल जला रहे हैं। विपक्ष खोद-खोद कर बात निकाल रहा है, बात का बतंगड़ बना रहा है, उनके राज-काज की खरी-खोटी सुना रहा है। अरे भाई, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, राम राज्य में भी तो शंबूक का सिर कटा था। तो यह कहने का क्या मतलब है कि मोदीजी मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारों को पता ही नहीं है कि राम राज्य का रास्ता तो मनुस्मृति से ही होकर गुजरता है।

अब पूरे एक माह देश के हर गली-कूचे में मोदीजी अवतरित होते रहेंगे। लोग-बाग 'कण कण में भगवान है' की प्रत्यक्ष अनुभूति करके आनंदित होंगे। भारत वर्ष में भयो उल्लास। 17 अक्टूबर तक यह उल्लास चलेगा सेवा संकल्प अभियान के साथ। आशीर्वाद का दीया से लेकर सेवा मेरा अभियान तक संघी गिरोह की सांस्कृतिक झलकियां दिखाई जाएगी। गुजरात में मोदीजी ने जो सेवा की है और अब पूरे भारत वर्ष में कर रहे हैं, उससे उत्साहित संघी गिरोह का हिंदुत्व हुंकारे भर रहा है और मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट थर-थर कांप रहे हैं। अभी तो सड़कों पर दीये जले हैं, मंदिरों से शंख-ध्वनि और आरती सुनी है लोगों ने। आने वाले दिनों में पूरे सेवा भाव से और-और मस्जिदों को खोद-खोद कर मंदिरों को निकाला जाएगा, कृष्ण जन्म भूमि को मुक्त कर भगवान कृष्ण को विराजमान किया जाएगा, आसाराम और राम रहीम हाथ में तिरंगा लेकर बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालेंगे, दिमागी नक्सलियों का कत्लेआम किया जाएगा। कांग्रेस राज के 60 सालों में जो-जो नहीं हुआ, वह सब सेवा भाव से किया जाएगा। धर्म स्थलों को राजनीति का अड्डा बनाया जाएगा और भाजपा कार्यालयों से धार्मिक आदेश जारी किए जायेंगे। धर्म को राजनीति में और राजनीति में धर्म को घुसेड़कर जो पाक रस तैयार किया जाएगा, उसे हिंदुत्व की सेवा में समर्पित किया जाएगा। लोगों को इस चरणामृत को चखाकर हिंदू राष्ट्र के लिए रास्ता साफ किया जाएगा। अयोध्या की झांकी को मथुरा, काशी से होते हुए पूरे देश में घुमाया जाएगा। इस झांकी में राम लीला तो होगी ही, भगवान कृष्ण की भी ऐसी-ऐसी लीलाएं होंगी कि लोग एप्सटीन फाइल तक भूल जाएंगे।

1925 से संघी गिरोह यही कर रहा है। लोगों को धर्म, भाषा, जात-पात में बांटना ही उसकी असली सेवा है। चुनाव हारते हैं, तो सेवा करने की उनकी रफ्तार बढ़ जाती है ; जीतते हैं, तो और बढ़ जाती है। इतनी सेवा के बाद भी वे परेशान हैं कि लोग आशीर्वाद का दीया लेकर उसकी बाती को जला क्यों नहीं रहे हैं। और लोग 2029 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हिंदू धर्म में दीया कब जलाया जाता है।

(लेखक व्यंग्यकार एवं अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं)

रेवड़ी नहीं, अधिकार चाहिए : प्रजा नहीं– नागरिक बनिए!

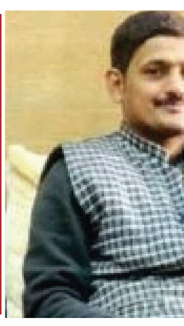

प्रमोद पंत

अहिंसा की राजनीति का एक कार्यकर्ता

'सरकार ने हमें क्या दिया? '

यह सवाल चुनावों और राजनीतिक बहसों में अक्सर सुनाई देता है।

लेकिन लोकतंत्र में इससे भी बड़ा सवाल है -

'सरकार ने हमें क्या दिया नहीं, बल्कि हमें नागरिक होने के नाते क्या मिलना चाहिए? '

यहीं से 'फ्री-बी/ रेवड़ी' और 'नागरिक हक' के बीच फर्क समझने की जरूरत पैदा होती है।

किसी गरीब परिवार को मुफ्त राशन मिले, किसान को आर्थिक सहायता मिले, महिला को गैस कनेक्शन मिले या किसी जरूरतमंद को पेंशन–ये सभी अपने-आप में गलत नहीं हैं। असली सवाल यह है कि लाभ किस उद्देश्य से दिया जा रहा है, उसका आधार क्या है और क्या वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर तथा अधिकार-संपन्न बना रहा है?

प्रजा और नागरिक में क्या अंतर है?

प्रजा शब्द में एक पुराने शासन की तस्वीर दिखाई देती है- राजा ऊपर है प्रजा नीचे। राजा देता है, प्रजा प्राप्त करती है और बदले में वफादारी की अपेक्षा की जाती है।

नागरिक की स्थिति अलग है

लोकतंत्र में नागरिक केवल सरकार से लेने वाला व्यक्ति नहीं है। वह अधिकारों का धारक, कर्तव्यों का पालन करने वाला और सरकार को जवाबदेह बनाने वाला व्यक्ति है।

सरल भाषा में हम इसे समझ सकते हैं....

प्रजा की मानसिकता
नागरिक की मानसिकता
राज्य/सरकार क्या देगी?
कानून के अनुसार मेरा क्या अधिकार है
कृपा की अपेक्षा कानून के अनुसार अधिकार
सरकार से डर सरकार से सवाल
लाभ पाने की कोशिश
व्यवस्था को जवाबदेह बनाना
चुनाव के समय याद हर दिन लोकतांत्रिक भागीदारी
'सरकार ने दिया ' 'यह मेरा नागरिक अधिकार है '

लोकतंत्र में नागरिक केवल सरकार से लेने वाला व्यक्ति नहीं है। वह अधिकारों का धारक, कर्तव्यों का पालन करने वाला और सरकार को जवाबदेह बनाने वाला व्यक्ति है।

गांधीजी का 'स्वराज': सरकार पर निर्भरता नहीं, नागरिक की शक्ति

महात्मा गांधी के लिए स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों को देश से बाहर करना नहीं था।

उन्होंने कहा कि वास्तविक स्वराज तब आएगा जब आम आदमी में इतनी क्षमता हो कि वह सत्ता के दुरुपयोग का विरोध और सत्ता को नियंत्रित कर सके। गांधी के अनुसार स्वराज कुछ लोगों के हाथ में सत्ता हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि जनता की क्षमता बढ़ाने का नाम है।

गांधीजी का एक महत्वपूर्ण विचार था कि अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे से जुड़े हैं। उनके अनुसार नागरिक केवल अधिकार मांगने का नाम नहीं, नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और राज्य के प्रति जिम्मेदारी भी निभाता है।

इसलिए गांधी के स्वराज में सवाल केवल यह नहीं था-

'सरकार मुझे क्या देगी '?

बल्कि यह भी था-

'मैं अपने गांव, समाज और देश के लिए क्या करूंगा और सरकार से उसके काम का हिसाब कैसे मांगूंगा '?

अम्बेडकर की दृष्टिः अधिकार केवल कागज पर नहीं, वास्तविक होने चाहिए

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल चुनाव की व्यवस्था नहीं माना। उनके विचारों में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की समझ तथा उनका वास्तविक उपयोग महत्वपूर्ण था। भारत सरकार के डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के संकलन में उनका यह विचार दर्ज है कि केवल असंतोष पर्याप्त नहीं, राजनीति और सामाजिक अधिकारों की न्यायसंगतता, आवश्यकता और महत्व की गहरी समझ भी जरूर है।

यानी नागरिक को यह पता होना चाहिए कि-

सरकार से मिलने वाली सुविधा और संविधान/कानून से मिलने वाला अधिकार एक ही चीज नहीं हैं।

'फ्री-बी' या 'रेवड़ी' क्या है?

'फ्रीबी' कोई कानूनी श्रेणी नहीं है। यह सार्वजनिक बहस में इस्तेमाल होने वाला शब्द है।

आमतौर पर ऐसी योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जिनमें सरकार किसी व्यक्ति या समूह को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर कोई वस्तु, सेवा या आर्थिक लाभ देती है।

उदाहरण के लिए-

ज़ मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली-पानी

ज़ मुफ्त वस्तुएं

ज़ नकद सहायता

ज़ चुनावी घोषणा के रूप में विशेष आर्थिक लाभ

ज़ कुछ वर्गों के लिए मुफ्त यात्रा या अन्य सुविधाएं

लेकिन हर मुफ्त सुविधा को 'रेवड़ी' कहना भी सही नहीं होगा।

गरीब को भोजन उपलब्ध कराना, बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा देना या गर्भवती महिला को मातृत्व सहायता देना- इनके पीछे सार्वजनिक कल्याण का उद्देश्य हो सकता है।

इसलिए किसी योजना को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि 'मुफ्त है या नहीं '।

यह देखना चाहिए-

किसके लिए? क्यों? किस कानून/नीति के तहत? कितने समय के लिए? और उसका सामाजिक उद्देश्य क्या है?

नागरिक हक की योजना क्या है?

नागरिक हक या कानूनी गारंटी वाली योजना में नागरिक को किसी कानून या स्थापित सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर अधिकार या सेवा प्राप्त होती है।

उदाहरणः

मनरेगा

ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की कानूनी गारंटी का ढांचा।

सूचना का अधिकार

सरकारी व्यवस्था से सूचना मांगने का कानूनी अधिकार।

शिक्षा का अधिकार

6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का कानूनी अधिकार।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

कानून के तहत निर्धारित पात्र आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा का ढांचा।

यहां नागरिक केवल यह नहीं कहता-

'सरकार मुझे कुछ दे दो '।

वह कह सकता है-

'कानून के अनुसार मेरा अधिकार है, इसलिए मुझे यह सेवा/सुविधा क्यों नहीं मिली '?

यही प्रजा और नागरिक के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर हैं।

एक आसान उदाहरणः राशन और रोजगार

मान लीजिए सरकार गरीब परिवार को मुफ्त राशन देती है।

यह सामाजिक सुरक्षा का उपाय हो सकता है।

लेकिन यदि उसी परिवार के वयस्क सदस्य को काम चाहिए और कानून रोजगार की गारंटी देता है, तो सवाल अलग है-

'मुझे मुफ्त अनाज कब मिलेगा '? के साथ-साथ

'मुझे काम का अवसर और मजदूरी कब मिलेगी '?

यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।

राशन भूख से बचाता है, लेकिन रोजगार व्यक्ति को आय और सम्मान के साथ जीने की क्षमता देता है।

तो क्या हर मुफ्त योजना गलत है? बिल्कुल नहीं।

यह समझना बहुत जरूरी है।

एक गरीब वृद्ध को पेंशन देना,
गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा देना,
दिव्यांग व्यक्ति को सहायता देना,
बच्चे को पोषण देना,
गर्भवती महिला को मातृत्व सहायता देना–

इनका उद्देश्य कमजोर व्यक्ति को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देना हो सकता है।

समस्या तब पैदा होती है जब कल्याण, अधिकार और राजनीतिक घोषणा के बीच का अंतर समाप्त हो जाए।

इसलिए किसी भी योजना को तीन सवालों से परखना चाहिए–

क्या यह राहत है?

तत्काल कठिनाई से बचाने के लिए।

क्या यह अधिकार है?

कानून या सार्वजनिक व्यवस्था के तहत मिलने वाली गारंटी।

क्या यह निवेश है?

शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार, सिंचाई, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी चीजें जो भविष्य की क्षमता बढ़ाती हैं।

जनता को क्या मांगना चाहिए?

जनता को केवल यह नहीं पूछना चाहिए-

'हमें क्या मुफ्त मिलेगा '?

जनता को चाहिए वह सरकार से पूछे-

ज़ रोजगार कहां है?

ज़ अच्छी और सस्ती शिक्षा कहां है?

ज़ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा कहां है?

ज़ किसान को उचित बाजार और उचित मूल्य कैसे मिलेगा?

ज़ सरकारी कार्यालय में मेरा काम समय पर क्यों नहीं होता?

और सबसे महत्वपूर्ण सवाल-

'सरकार मेरे पैसे का हिसाब कब देगी '?

यही सवाल नागरिक को लाभार्थी से भागीदार बनाता है।

प्रजा मत बनिए, जागरूक नागरिक बनिए

किसी नेता के हाथ से मिलने वाली चीज देखकर केवल यह मत पूछिए-

'मुझे क्या मिला? '

यह भी पूछिए-

'मेरा अधिकार क्या है? '

'सरकार ने यह पैसा कहाँ से लिया? ' 'इस योजना का कानून क्या है? '

'इसका लाभ किसे और क्यों मिल रहा है? '

'क्या इससे मेरी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी? '

और सबसे जरूरी–

'क्या मैं सरकार का लाभार्थी हूं या लोकतंत्र का जागरूक नागरिक? '

गांधी का स्वराज हमें सत्ता का केवल उपभोक्ता नहीं, सत्ता को जवाबदेह बनाने वाला नागरिक बनने की दिशा दिखाता है। लोकतंत्र की असली सफलता इस बात में नहीं है कि सरकार ने जनता को कितनी चीजें मुफ्त दीं।

असली सफलता तब है जब देश का गरीब भी कह सके–

'मैं किसी की कृपा पर नहीं, अपने अधिकार और सम्मान के साथ जीता हूं।

और जब जनता यह कहने लगे–

'सरकार हमारी मालिक नहीं–हमारे प्रति जवाबदेह संस्था है।

तभी प्रजा से नागरिक और शासन से स्वराज की यात्रा पूरी होती है।

भाजपा विकास कानून व्यवस्था पर तो सपा योजनाओं और पीडीए पर दांव लगा रही

-कांतिलाल मांडोत-

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मुद्दे जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के बयानों से साफ है कि भाजपा इस चुनाव को सरकार के करीब दस साल के कामकाज, कानून-व्यवस्था, विकास, धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों और संगठन की ताकत के आधार पर लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में महिलाओं, छात्राओं, युवाओं, रोजगार और सामाजिक न्याय को चुनावी बहस का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम सपा का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि इसमें कांग्रेस और बसपा की भूमिका भी सीटों के परिणाम पर असर डाल सकती है। भाजपा के सामने सबसे बड़ा तर्क यह है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार की प्राथमिकताओं को विकास और कानून-व्यवस्था से जोड़ा गया है। भाजपा नेता लगातार एक्सप्रेस-वे, निवेश, उद्योग, बुनियादी ढांचे और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को सामने रख रहे हैं। पार्टी की चुनावी तैयारी में सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर भी जोर है।

रोजगार भाजपा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले छह महीनों में एक लाख नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की है। सितंबर में भी विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सरकारी रोजगार पोर्टल पर सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों को एक साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसी के साथ शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

यही वह क्षेत्र है जहां विपक्ष भाजपा को घेरना चाहता है। समाजवादी पार्टी का तर्क है कि केवल सरकारी नियुक्तियां पर्याप्त नहीं हैं और युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक सहायता का व्यापक ढांचा जरूरी है। अखिलेश यादव की नई घोषणाओं में कन्या विद्याधन योजना को फिर शुरू करने और बारहवीं पास छात्राओं को पचास हजार रुपए देने का वादा शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सालाना चालीस हजार रुपए की सहायता और छात्राओं को लैपटॉप जैसी घोषणाएं भी की गई हैं। सपा की रणनीति का दूसरा आधार सामाजिक समीकरण है। पार्टी पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा 33 सीटों पर रही। यह परिणाम विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे इतना जरूर स्पष्ट हुआ कि राज्य का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण गत चुनावों की तुलना में बदला है।

भाजपा इसी चुनौती का जवाब अपने संगठन और सरकार के कामकाज के माध्यम से देने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचना, महिलाओं, युवाओं, किसानों, छोटे कारोबारियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों से संपर्क बढ़ाना शामिल है। मुख्यमंत्री योगी की लगातार जिलावार यात्राएं भी इसी अभियान का हिस्सा हैं। कांग्रेस की स्थिति अलग है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह सीटें जीती थीं और सपा के साथ उसका गठबंधन रहा था। 2027 में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का तालमेल किस रूप में बनता है, यह विपक्ष की चुनावी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह राज्य में अपना संगठन और स्वतंत्र राजनीतिक आधार कितना मजबूत कर पाती है। यदि वह प्रभावी सीट हिस्सेदारी और मजबूत उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरती है तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है।

बसपा की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मायावती ने 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। बसपा का पारंपरिक दलित आधार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए बसपा कितने वोट अपने साथ रखती है और किन क्षेत्रों में उसका प्रभाव कायम रहता है, यह भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण चुनावी गणित बन सकता है। बसपा के सामने चुनौती अपने पुराने संगठन और सामाजिक आधार को फिर सक्रिय करने की है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में किया 'विकसित भारत संकल्प ज्योति यात्रा' का शुभारंभ

- मोदी के 25 वर्ष भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय: अमित शाह
- मुख्यमंत्री सैनी ने मशाल थामी, युवाओं से योगदान का आह्वान किया
- सिग्नेचर टावर पर मशाल स्थापित, युवाओं से विकसित भारत का आह्वान

संवाददाता

गुरुग्राम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को साइबर नगरी गुरुग्राम से 'विकसित भारत संकल्प ज्योति यात्रा' का भव्य शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में देश और प्रदेश के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा की मशाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपते हुए प्रदेशवासियों को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का मजबूत संदेश दिया। इस अवसर पर पूरा पंडाल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा और हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक स्वर्णिम और युगांतकारी अध्याय है। एक साधारण गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति ने अपनी असाधारण क्षमता और जनसमर्थन से 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें गरीबों का कल्याण, देश की आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, नक्सलवाद का खात्मा और अयोध्या में श्रीराम मंदिर व काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण शामिल है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते देश के करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसी सेवा और उपलब्धियों के सफर को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 'सेवा ज्योति यात्रा' का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को सौंपी मशाल

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हजारों युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जनभागीदारी के जरिए 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। संबोधन के पश्चात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के प्रमुख मार्गों से पैदल यात्रा करते हुए सिग्नेचर टावर के पास यात्रा की मशाल स्थापित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मशाल युवाओं को सौंपते हुए कहा कि हरियाणा और देश का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समृद्ध और समस्यामुक्त बने। इस भव्य आयोजन में युवाओं का जोश देखते ही बनता था और सभी ने मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी ताकत झोंक देने का संकल्प लिया।

प्रमुख नेताओं की रही गरिमामयी उपस्थिति

इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉ. सुधा यादव सहित गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों के विधायक, मेयर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी गणमान्य अतिथियों ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान को जन-जन तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता दोहराई और केंद्र तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को घर-घर तक पहुँचाने का आह्वान किया। प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे यह पूरा आयोजन बेहद सफल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

स्वैच्छिक रक्तदान में लगातार तीसरे साल हरियाणा देश में अव्वल 5.89 लाख यूनिट रक्त एकत्रित कर रचा इतिहास

- ब्लड सेंटर्स के लिए पहला आपदा प्रबंधन प्लान जारी
- राज्य ने 2,000 कैंप के लक्ष्य के मुकाबले 8,189 कैंप लगाए
- स्वैच्छिक रक्तदान दर 92 फीसदी तक पहुंची
- हरियाणा ने ब्लड सेवाओं में इमरजेंसी की तैयारी को शामिल किया

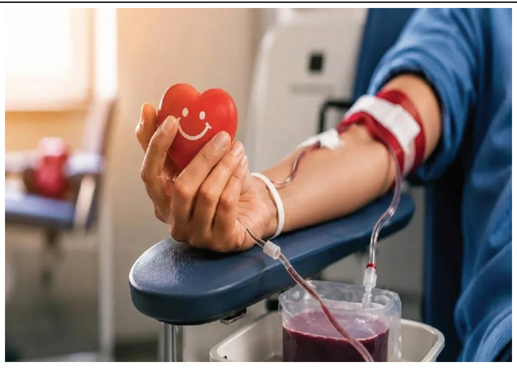

संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा लगातार तीसरे साल स्वैच्छिक रक्तदान के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है। राज्य ने 3.30 लाख यूनिट रक्त और 2,000 रक्तदान शिविरों के लक्ष्य के मुकाबले 8,189 शिविर आयोजित कर 5.89 लाख यूनिट रक्त एकत्रित किया। राज्य में कुल ब्लड कलेक्शन में स्वैच्छिक रक्तदान की हिस्सेदारी 92 प्रतिशत रही।

लक्ष्य से चार गुना अधिक लगाए रक्तदान शिविर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा ने निर्धारित लक्ष्य से चार गुना से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित किए। वहीं, केंद्र के 3.30 लाख यूनिट के लक्ष्य की तुलना में राज्य ने करीब 78 प्रतिशत अधिक रक्त एकत्र किया। उन्होंने कहा कि लगातार तीन वर्षों तक देश में स्वैच्छिक रक्तदान में पहला स्थान हासिल करना राज्य के लिए गर्व की बात है। राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की ओर से 2025 में प्रति दस लाख आबादी पर सर्वाधिक रक्तदान दर्ज करने के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। डॉ. मिश्रा ने इस उपलब्धि का श्रेय ब्लड सेंटर की टीमों, स्वैच्छिक रक्तदाताओं, युवा नेटवर्क, एनजीओ, रेड क्रॉस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस से जुड़े लोगों को दिया। राज्य में 162 ब्लड सेंटर संचालित हैं, जिनमें 92 प्रतिशत में कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की सुविधा उपलब्ध है।

आपदा प्रबंधन प्लान भी तैयार

डॉ. मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड सेंटरों के लिए राज्य का पहला आपदा प्रबंधन प्लान तैयार किया है। इसका उद्देश्य रक्त की सुरक्षा मजबूत करने और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि विशेष रक्तदान अभियानों से भी बड़ी मात्रा में रक्त जुटाया गया। राज्यव्यापी अभियान से 10,183 यूनिट और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350 वीं वर्षगांठ से जुड़े अभियानों से 40,224 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुरक्षित, समान, सुलभ और समय पर रक्त एवं रक्त घटकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नियमित स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान जारी रखने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष पूरेः शिवसेना गुरुग्राम ने सरकारी स्कूल के बच्चों को बांटी शैक्षणिक सामग्री

संवाददाता

गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए शिवसेना गुरुग्राम की टीम ने एक विशेष जनहित कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान टीम के सदस्य एक सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां विद्यार्थियों को उत्साह के साथ शैक्षणिक सामग्री और मिठाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत की गई और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही किसी भी समाज के विकास का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में जरूरतमंद विद्यार्थियों की हरसंभव मदद करना हम सभी का नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी है। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ शिवसेना हरियाणा के राज्य प्रमुख नीरज सेठी द्वारा किया गया। विद्यार्थियों की सहायता के साथ-साथ इस अवसर पर जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में आसपास के क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और इस नेक पहल की सराहना की। शिवसेना पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निर्बाध सेवा भाव और समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनके कार्य देश के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। संगठन भविष्य में भी ऐसे सामाजिक, शैक्षणिक और जनहित के कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखेगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ललित क्रांतिकारी, राज्य सचिव सुमित मलिक, जिला प्रवक्ता संजीव ढांडा, जिला सचिव गौरव वशिष्ठ, जिला उप प्रमुख रवि ग्रोवर, ब्लॉक प्रमुख मनोज कुमार, जिला कोषाध्यक्ष सुभाष सारवन, साहिल सारवन, तुषार सारवन, कीर्ति प्रधान, अनुराग सिंह, रजत ग्रोवर और वाल्मीकि सभा के प्रधान ज्ञानेश्वर सारवन सहित अनेक शिवसैनिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सोहना में नवनिर्मित फव्वारा चौक निर्माण में घोटाला उजागर होने की संभावना, एसीबी ने शुरू की जांच

- भ्रष्टाचार आरोपों पर ब्यूरो ने नगर परिषद से दस्तावेज तलब किए
- जांच बढ़ने से संलिप्त कई परिषद अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना

संवाददाता

सोहना। कस्बे में नवनिर्मित फव्वारा चौक निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं व घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरंभ कर दी है। ब्यूरो ने परिषद अधिकारियों से योजना से संबंधित दस्तावेजों को तलब किया है। किंतु खबर है कि परिषद ने अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। वहीं उक्त मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना प्रबल रूप से मुखर होने लगी है, जिन्होंने निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरती हैं। सोहना नगर परिषद अपनी कारगुजारियों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रही है। वर्तमान में एलईडी लाइट घोटाला इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसमें 11 आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपराधिक मामला दर्ज कराया है। ब्यूरो की उक्त कार्रवाई से परिषद अधिकारियों में हड़कंप व बेचैनी व्याप्त है। इसी क्रम में करीब तीन वर्ष पूर्व नगरपरिषद द्वारा निर्मित कराए गए फव्वारा चौक निर्माण की परतें भी खुलने की संभावना है। मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है तथा परिषद अधिकारियों से योजना से संबंधित दस्तावेज तलब किए जाने के फरमान जारी किए हैं। किंतु बताते हैं कि परिषद ने अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।

क्या थी योजना

नगर परिषद ने करीब 3 वर्ष पूर्व कस्बे के ऐतिहासिक व प्राचीन फव्वारा चौक के सौंदर्यीकरण किए जाने की योजना तैयार की थी। योजना के तहत पुलिया निर्माण, फव्वारा सौंदर्यीकरण, तीन मुख्य द्वार, बेंच, लाइटिंग, म्यूजिकल फव्वारे आदि शामिल थे। उक्त योजना पर कुल 2 करोड़ पांच लाख रुपए की राशि खर्च की जानी तय थी। जिसके निर्माण के लिए परिषद ने जुलाई, 2023 में निजी एजेंसी को ठेका दिया था। निर्माण के लिए एक वर्ष का समय निश्चित किया गया था। परंतु एजेंसी ने निर्धारित समय में कार्य को पूरा नहीं किया था। इसके अलावा निर्माण कार्य में ढेरों खामियां थीं। मामले की शिकायत कई बार नगरपरिषद अधिकारियों से लेकर एसडीएम सोहना, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा को भी की गई थी। हैरत की बात है कि अधिकारियों ने कार्य पूरा होने से पहले ही एजेंसी को लाखों रुपए की राशि परिषद कोष से निकालकर दे दी थी।

शिकायत पहुंची एसीबी में

मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष पहुंचने पर ब्यूरो ने अपने स्तर पर जांच प्रारंभ कर दी है। शिकायतकर्ता अमित गर्ग कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, जिसकी शिकायत एसीबी को की गई थी। ब्यूरो ने परिषद अधिकारियों से दस्तावेज उपलब्ध कराने के फरमान दिए हैं।

वंदे मातरम' नारों के साथ मंत्री अनिल विज ने मशाल प्रज्वलित की और ज्योति स्थापित कर कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह

संवाददाता

अंबाला छावनी। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कांग्रेस की 'स्कैम' (घोटाले) करने वाली सरकार को हटा कर भारतीय जनता पार्टी की 'सेवा' करने वाली सरकार बनाई है, जिसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री का आभारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हम सबका साझा संकल्प है। ऊर्जा मंत्री बुधवार को अंबाला शहर की पुलिस लाइन में आयोजित 'सेवा ज्योति यात्रा' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित किया गया था।

दीए से दीया जलाकर अंधेरा मिटाने का संदेश

मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्ष 2001 में भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लेकर आज तक वे निरंतर देश की सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि 'सेवा-संकल्प' में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं–एक 'सेवा' और दूसरा 'संकल्प'। उन्होंने कहा कि 'सेवा-संकल्प' में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं–एक 'सेवा' और दूसरा 'संकल्प'।हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में और कैसे जनसेवा कर सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार तो काम कर रही ही है, साथ ही हम सबको भी सेवा के कार्यों से जुड़ना होगा। इसी उद्देश्य से 'सेवा ज्योति यात्रा' निकाली जा रही है, जो हर मोहल्ले, गांव और शहर तक पहुंचेगी ताकि 'दीए से दीया और ज्योत से ज्योत जलाकर देश से हर तरह का अंधेरा मिटाया जा सके। '

कार्यक्रम में दिखा भारी उत्साह और उमड़ी भीड़

कार्यक्रम की शुरुआत में ऊर्जा मंत्री अनिल विज का डीसी सचित गुप्ता और अन्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना। संबोधन के पश्चात ऊर्जा मंत्री अनिल विज और पूर्व राज्यमंत्री असीम गोयल ने संयुक्त रूप से मशाल जलाकर 'सेवा ज्योति यात्रा' की शुरुआत की। यह यात्रा पुलिस लाइन से शुरू होकर ओल्ड सेशन कोर्ट तक गई, जहां ज्योति स्थापित की गई। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने 'वंदे मातरम' के जोरदार नारे लगाकर उपस्थित कार्यकर्ताओं और नागरिकों में भारी जोश का संचार किया। अंबाला छावनी से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता 42 बसों के काफिले के साथ इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री असीम गोयल, पूर्व विधायक पवन सैनी, नगर निगम मेयर अक्षिता सैनी, नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मंडियों में धान खरीद की बदहाली पर 'आप' के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का का फूटा गुस्सा

▶▶ बोले- किसान आत्महत्या को मजबूर, सरकार कर रही है इवेंट बाजी

संवाददाता

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सुशील गुप्ता ने राज्य की मंडियों में धान खरीद की व्यवस्था को लेकर सैनी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक नाकामी और मनमानी शर्तों के कारण आज हरियाणा का किसान अपनी ही फसल बेचने के लिए दर-दर भटकने और जान देने को मजबूर हो चुका है। अन्नदाता पिछले 15-15 दिनों से मंडियों में रातें बिताने को विवश हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

सीएम पर झूठे दावे करने और सिंगापुर में इवेंट बाजी का आरोप

डॉ. सुशील गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरे प्रदेशों में जाकर झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं और किसानों से दावा करते हैं कि हरियाणा में 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत सोमवार को कैरू स्थित खंड विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय परिसर में 'सेवा सेतु कैंप' का आयोजन किया गया। एसडीएम संदीप कुमार ने शिविर का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की जानकारी ली।उन्होंने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री गंगाजल हाथ उठाकर उन 24 फसलों के नाम सार्वजनिक करें, जिनकी खरीद वास्तव में एमएसपी पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि करनाल के घरौंडा में धान न बिकने और अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान एक किसान द्वारा जहर पीने की दर्दनाक घटना इसका जीता-जागता प्रमाण है।

मंडियों में बदइंतजामी और खुले में पड़ा धान

'आप' प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की मंडियों में 9 लाख टन से अधिक धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मौसम खराब होने और बारिश की चेतावनी के बावजूद खरीद सिर्फ 30 प्रतिशत और उठान मात्र 17 प्रतिशत ही हुआ है, आम आदमी पार्टी (आप) हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सुशील गुप्ता ने राज्य की मंडियों में धान खरीद की व्यवस्था को लेकर सैनी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पोर्टल के रजिस्ट्रेशन, नमी और गेट पास की जटिल शर्तों में किसानों को जानबूझकर उलझाया जा रहा है ताकि वे औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को फसल बेचने पर मजबूर हों। पार्टी ने चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत खरीद की प्रक्रिया तेज करे, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा।

वेदप्रकाश मंगला की अंतिम विदाई बनी किसी के जीवन की नई रोशनी

संवाददाता

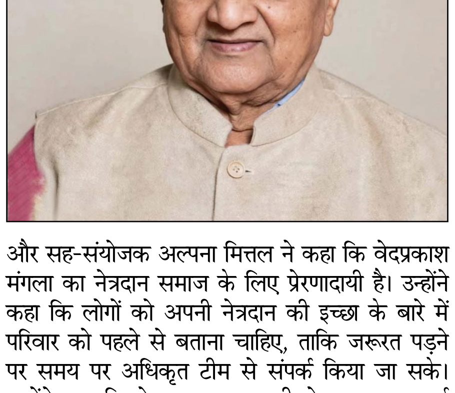

पलवल। वयोवृद्ध समाजसेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता वेदप्रकाश मंगला के निधन के बाद उनके परिवार ने नेत्रदान करवाकर समाज सेवा की मिसाल पेश की। हरियाणा भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला सहित परिवार के सदस्यों आनंद मंगला, विजय मंगला, संजय मंगला, पवन मंगला और राहुल मंगला ने आपसी सहमति से नेत्रदान का निर्णय लिया। पलवल डोनर्स क्लब 'ज्योतिपुंज' की सह-संयोजक अल्पना मित्तल के सहयोग से नागरिक अस्पताल की नेत्रदान टीम ने प्रक्रिया पूरी करवाई। नेत्र विशेषज्ञ डॉ. मनीषा चौधरी के निर्देशन में नेत्रदान काउंसलर दर्शन, ओए ऑप्टो ऋषिपाल, सुमित और धर्मपाल की टीम ने निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत नेत्रदान कराया। दीपक मंगला ने कहा कि उनके पिता ने जीवन भर समाजसेवा और जरूरतमंदों की सहायता को प्राथमिकता दी। उनके निधन के बाद नेत्रदान करवाना उनके सेवाभाव को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यदि नेत्रदान से किसी व्यक्ति के जीवन में रोशनी आती है तो यह उनके पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने लोगों से नेत्रदान के लिए आगे आने की अपील की। पलवल डोनर्स क्लब 'ज्योतिपुंज' के मुख्य संयोजक डॉ. विकास मित्तल और सह-संयोजक अल्पना मित्तल ने कहा कि वेदप्रकाश मंगला का नेत्रदान समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी नेत्रदान की इच्छा के बारे में परिवार को पहले से बताना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर समय पर अधिकृत टीम से संपर्क किया जा सके। उन्होंने कहा कि नेत्रदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दौरान क्लब और नागरिक अस्पताल की टीम ने मंगला परिवार के इस सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया।

संक्षिप्त डायरी

मुरादाबाद में जैन समाज की रथयात्रा में गूंजा संदेश

एजेंसी

मुरादाबाद । उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एमडीए के तत्वावधान में पर्यूषण पर्व के समापन पर सोमवार को मंदिर से रथयात्रा निकाली गई। यात्रा के आगे बढ़ते ही भगवान महावीर सहित जैन समाज के विद्वानों का जयघोष होने लगा। सानिध्य भद्रबाहु सागर महाराज का रहा। रथयात्रा में बड़ी संख्या में झांकियों के प्रदर्शन से जैन समाज संदेश प्रसारित किए गए। भगवान श्रीजी के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु उमड़े रहे। रथयात्रा के मंदिर पहुंचने पर अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर गुरु की पूजा की गई। शांतिधारा आशा जैन, धीरज जैन एवं नीरज जैन के परिवारों ने कराई। लौंग की जयमाल का सौभाग्य सुमन जैन, रितेश जैन,अर्पित जैन के परिवारों को प्राप्त हुआ। इसमें दीपक जैन, सीमा जैन, तुषार जैन, परिवार तथा मधु जैन, विकास जैन, आग्रती जैन परिवार भी शामिल रहे। प्रवचन करते हुए भद्र बाहु सागर महाराज ने कहा रथयात्रा से प्रभावना बढ़ती है। रथयात्रा में महिलाएं केसरिया एवं पुरुष वर्ग सफेद ड्रेस में रहे। टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन अपने परिवार सहित शामिल रहे। रथयात्रा में अध्यक्ष संदीप जैन सहित नीरज जैन, विकास जैन, राजीव जैन, महिला जैन इकाई की अध्यक्ष सुषमा जैन,सीमा जैन, श्रुति जैन, छवि जैन, शिवानी रहीं।

ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बोलेरो पलटी, पहिए की चपेट में आने से चालक की मौत

एजेंसी

हाथरस। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में सासनी कोतवाली क्षेत्र में सासनी-इगलास रोड पर रविवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में बोलेरो चालक की मौत हो गई। गोबर की खाद से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक ने ट्रैक्टर चालक को रोकने का प्रयास किया और उसके पीछे दौड़ा। आरोप है कि इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने वाहन उसकी ओर मोड़ दिया, जिससे बोलेरो चालक ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल युवक को आसपास मौजूद लोगों और उसके साथी कर्मचारियों ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई है। बताया गया कि अमित अविवाहित था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल पर छोड़े गए ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपित ट्रैक्टर चालक की पहचान और तलाश में जुटी है। सासनी कोतवाली के इंस्पेक्टर विपिन चौधरी ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से हादसे के संबंध में जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उपलब्ध तथ्यों और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गांधी महोत्सव में दुकानदारों का अनुभव, कहीं लाभ तो कहीं गम

एजेंसी

वाराणसी, । वाराणसी में चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में विगत एक माह से चल रहे गांधी महोत्सव को लेकर सोमवार को दुकानदारों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गांधी महोत्सव में दुकानदारों का अनुभव कहीं लाभ तो कहीं गम जैसा रहा है। गांधी महोत्सव में 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 25 हजार रुपये प्रति दुकान लेने वाले दुकानदारों ने औसतन कमाई की है। महोत्सव में कपड़े पर प्रिंटिंग की दुकान लगाने वाले दुकानदार बाबू ने बताया कि वह तो एक माह में इतना भी नहीं कमा सके कि जिससे उनके दुकान का शुल्क निकाल पाए। गांधी महोत्सव में खादी की दुकान के दुकानदार सुनील यादव ने बताया कि जैसे सर्दियों की शुरूआत होती है, तब किसी मेले में रौनक आती है। लेकिन तब तक गांधी महोत्सव समाप्त हो चुका होगा। राष्ट्रपिता गांधी जी के आदर्शों को मानने वाले लोगों की बहुतायत होने के बावजूद इस गांधी महोत्सव में खादी के कपड़े और सदरी लेने वालों की रुचि कम दिखाई दी। जिसका मुख्य कारण अभी सर्दियों का शुरू न होना है। गांधी महोत्सव में पहुंचे ग्राहक गौरव ने बताया कि किसी भी पारंपरिक मिले और महोत्सव में खरीदारी करने वाले प्रमुख लोगों में महिलाएं होती हैं। गांधी महोत्सव में महिलाओं की उतनी संख्या नहीं है, जितनी अपेक्षाकृत होनी चाहिए। वह भी अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद कर जा रहे हैं।

यात्री बस ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई, नेपाल के दो मजदूरों की मौत, 11 घायल

एजेंसी

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मोहम्मदाबाद गांव के पास ओवरब्रिज पर सोमवार की सुबह लद्दाख से मजदूरी कर लौट रहे नेपाल के मजदूरों की बस ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि लद्दाख से मजदूरी कर लौट रहे नेपाल के मजदूरों की बस मोहम्मदाबाद गांव के सामने हाईवे के ओवरब्रिज पर सीमेंट की बोरी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस में सवार दो यात्रियों भगीराम (58) और सुर वशिष्ठ (45) की मौत हो गई, जबकि मृतक भगीराम की पुत्रवधू पुष्पा, बेटा विनोद, पुष्पा के गोद का बच्चा निखिल(02), ओम बहादुर राहुल उसकी पत्नी ओसा, ध्रुव प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद व उसकी पत्नी रीता देवी, राजेश, आरोही (01) पुत्र राजेश, नूर वशिष्ठ, टेक बहादुर, देवा, ओमफा सिंह, कमल, मनीराम, बस चालक धीरेंद्र व परिचालक प्रकाश समेत 11 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। क्रेन मदद से क्षतिग्रस्त बस व ट्रैक्टर ट्रॉली को हाईवे से हटवाया गया। एएसपी ने बताया कि प्रथमदृष्टया जांच में ये पाया गया कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की छानबीन कर रही है।

नदी, नहर और तालाब में नहाते समय बरतें विशेष सतर्कता : जिलाधिकारी

एजेंसी

देवरिया । जिले में नदी, नहर और तालाबों के जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सोमवार को जनपदवासियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नदियों, नहरों और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में नहाने अथवा तैरने के लिए जलाशयों में जाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में लगातार ऐसी घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, जिनमें बच्चे एवं युवा नदियों, नहरों और तालाबों में नहाने अथवा तैरने के लिए पहुंच रहे हैं। पानी की गहराई और बहाव की सही जानकारी न होने के कारण अचानक डूबने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जब तक जलस्तर सामान्य न हो जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति नदी, नहर अथवा तालाब में नहाने या तैरने के लिए

मजदूरी करने जा रहा 32 वर्षीय युवक उल्ल नदी में डूबा, पीएसी फ्लड टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

एजेंसी

लखीमपुर । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सोमवार की सुबह एक बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा सामने आया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत रपटा पुल के पास मजदूरी पर जा रहा एक 32 वर्षीय युवक अचानक उल्ल नदी के तेज बहाव और गहरे पानी में समा गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत व बचाव कार्य के लिए सीतापुर से पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र पुलिस) की विशेष फ्लड टीम को बुलाया गया। गोताखोरों द्वारा नदी में युद्धस्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन देर रात तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका था। प्राप्त

जानकारी के अनुसार, दुर्घटना सोमवार सुबह लगभग 8:00 बजे की है। लखीमपुर के लखपेड़ा गंज का निवासी 32 वर्षीय जाबिर अली, पुत्र मोहम्मद नबी, रोज की तरह सोमवार की सुबह भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करने शहर जा रहा था। जब वह कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत जुलाहन पुरवा के पास स्थित रपटा पुल से होकर गुजर रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर या जलस्तर तेज होने के कारण नदी के गहरे पानी में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जाबिर को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह देखते ही देखते नदी के तेज बहाव में बहता चला गया और ओझल हो गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने युवक को पानी में डूबते देखा, मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अपने स्तर पर उसे बचाने का प्रयास किया और साथ ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और परिजनों को दी। सूचना पाते ही रामापुर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंचे। नदी के बहाव और गहराई को देखते हुए साधारण स्तर पर रेस्क्यू करना संभव नहीं था, जिसके चलते जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। घटना की संवेदनशीलता और युवक की जान बचाने की प्राथमिकता को देखते हुए पड़ोस के जिले सीतापुर से पीएसी की विशेषज्ञ फ्लड (बाढ़) टीम को तत्काल मौके पर बुलाया गया। सीतापुर से पहुंची पीएसी टीम ने स्थानीय पुलिस और अनुभवी स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पीएसी के कुशल गोताखोर बोट (नाव) और आधुनिक उपकरणों की मदद से उल्ल नदी के विभिन्न हिस्सों में जाबिर की तलाश में लगातार गोता लगा रहे हैं। इस संबंध में रामापुर चौकी प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी।

नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी पुलिस और पीएसी की फ्लड टीम मिलकर नदी के बड़े हिस्से को खंगाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता युवक को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, हादसे की खबर सुनते ही जाबिर अली के घर में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन और ग्रामीण भी घटना स्थल पर पहुंच गए। जाबिर अपने परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य था और सुबह हंसते-खेलते काम पर निकला था। उसकी अचानक इस तरह नदी में डूबने की खबर ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। गांव और मोहल्ले के लोग पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने में लगे हैं, जबकि सबकी निगाहें नदी किनारे चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। समाचार लिखे जाने तक बचाव दल द्वारा कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बावजूद लापता जाबिर अली का कोई पता नहीं चल सका है। जलधारा के बहाव को देखते हुए सर्च ऑपरेशन का दायरा डाउनस्ट्रीम (नदी के निचले बहाव वाले क्षेत्र) की तरफ भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में पूरी निष्ठा से जुटी हुई है।

शिक्षक दम्पति हत्याकांड के दो आरोपित गिरफ्तार , जेल

एजेंसी

सुलतानपुर । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर के थाना कादीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुम्हीडड़िया में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। कादीपुर पुलिस एवं एसओजी टीम ने दो आरोपित को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की धनराशि एवं घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने सोमवार को बताया कि थाना कादीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुम्हीडड़िया स्थित मनराजी शिक्षण संस्थान में मुकेश कुमार सिंह पुत्र स्व. रामबदल सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती विनीता सिंह की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उक्त घटना के संबंध में 29 सितंबर को मृतक के भाई अखिलेश सिंह पुत्र स्व. रामबदल सिंह निवासी ग्राम कुम्हीडड़िया की लिखित तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी /सर्विलांस सहित कुल पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों का संकलन कराया गया। आज बुढ़ाना पुल के पास बड़ी नहर पुलिया के पास से आरोपित राकेश कुमार यादव पुत्र स्व. लहुरी यादव, निवासी ग्राम कुम्ही डडिया, एवं आशीष यादव उर्फ डब्बू यादव पुत्र हरिनाथ यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में राकेश कुमार यादव ने बताया कि वह मनराजी शिक्षण संस्थान ग्राम कुम्हीडड़िया थाना कादीपुर में बस चलाने एवं कम्प्यूटर पढ़ाने का कार्य करता था तथा आशीष यादव उर्फ डब्बू यादव उसके पड़ोस में ही रहने वाला एवं उसका पट्टीदार है। राकेश की माली हालत काफी कमजोर है । दोनों ने शिक्षण संस्थान में चोरी करने की योजना बनाई । राकेश को स्कूल एवं कार्यालय के संबंध में तथा सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के संबंध में पूर्ण जानकारी थी । 28 सितंबर की रात्रि में दोनों चोरी की नीयत से वहां गए ।

देवरिया : बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता का एक दिन का वेतन रोकने का जिलाधिकारी ने दिए आदेश

एजेंसी

देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में जल संसाधन से जुड़े विभागों की बैठक कर विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जल निगम (ग्रामीण एवं शहरी), बाढ़ खंड, सिंचाई, तथा नलकूप विभाग के कार्य प्रगति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग से जुड़ी प्रगति समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता, नलकूप सलेमपुर का एक दिन का वेतन रोके जाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठकों में अनुपस्थित रहने को कतई क्षम्य नहीं होगा और सभी अधिकारी बैठक में विभाग की पूर्ण प्रगति के विवरण के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित रहने अथवा अपूर्ण आंकड़े पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय परियोजनाओं एवं विकास कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा में

गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और कार्यों में अनावश्यक देरी न होने दी जाए। जल निगम की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने पाइप लाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़कों का रिस्टोरेशन समय से पूरा कराया जाए, ताकि आवागमन में आमजन को परेशानी न हो।अधिशासी अभियंता बाढ़ द्वारा बताया गया कि सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। सरयू नदी के जलस्तर में कुछ आंशिक वृद्धि हुई है। किसी भी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। फिर भी सभी तटबंधों पर सतर्क एवं सजग निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ खंड के कार्यों की समीक्षा में जलस्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों को नियमित रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बाढ़ एवं कटान से बचाव से जुड़े कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए आवश्यक तैयारियां समय से पूरी रखने को कहा। सिंचाई विभाग की योजनाओं की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने नहरों में पानी की उपलब्धता और टेल तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने नहरों की ब्लॉकवार स्थिति का विवरण तैयार रखने तथा आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई कराने को कहा। नलकूप विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी राजकीय नलकूपों को क्रियाशील रखने तथा किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। यांत्रिक एवं विद्युत खराबी के कारण बंद नलकूपों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराने तथा नए नलकूपों की स्थापना एवं पुराने नलकूपों के मरम्मत कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिशासी अभियंता बाढ़, अधिशासी अभियंता सिंचाई, अधिशासी अभियंता नलकूप देवरिया, लघु सिंचाई के सहायक अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मीरजापुरः वन भूमि पर विद्यालय निर्माण, बिना एनओसी काम रोकने का दावा

एजेंसी

मीरजापुर । उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में ड्रमंडगंज क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य लहुरियादह गांव में निमार्णाधीन उच्च प्राथमिक विद्यालय का काम रविवार को वन विभाग ने रुकवा दिया। वन विभाग का स्पष्ट दावा है कि विद्यालय के लिए चुनी गई जमीन उसकी आराजी संख्या 730 और 732 में दर्ज वन भूमि है। विभाग के अनुसार इस जमीन पर विद्यालय निर्माण के लिए उसकी एनओसी नहीं ली गई थी। इसी आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोक दिया। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2023 में गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से की गई थी। विद्यालय स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो सका। पूर्व डीएम द्वारा अपने इस्तीफे के बाद वीडियो में लहुरियादह स्कूल का मुद्दा उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने 30 सितंबर को जमीन चिह्नित कर निर्माण शुरू कराया था। ग्रामीणों के मुताबिक नींव की खुदाई और निर्माण सामग्री गिराने का काम चल रहा था। रविवार को वन विभाग की टीम पहुंची और जमीन को वन विभाग की बताते हुए काम रुकवा दिया। वन क्षेत्राधिकारी ड्रमंडगंज रविशंकर शर्मा ने सोमवार को मामले में बताया कि निर्माण स्थल वन विभाग की आराजी संख्या 730 और 732 में आता है। बिना विभागीय अनुमति और एनओसी के वहां निर्माण कराया जा रहा था, इसलिए कार्य रुकवा दिया गया है। वहीं विद्यालय निर्माण के लिए अधिकृत प्राथमिक विद्यालय लहुरियादह के प्रधानाध्यापक गंगा शंकर ओझा ने कहा कि वन विभाग द्वारा निर्माण रोके जाने की उन्हें जानकारी नहीं है। काम रुकने से विद्यालय निर्माण अधर में लटक गया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से वन विभाग के दावे और निर्माण की भूमि की स्थिति स्पष्ट कराकर विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कार्रवाई पर उठाए सवाल राजगीर बद्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि रविवार को वन विभाग की टीम ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर काम रुकवा दिया और कन्नी, फावड़ा व तगाड़ी आदि सामान उठा ले गई। ग्रामीण हरिलाल ने कहा कि यदि जमीन वन विभाग की थी तो निर्माण शुरू कराने से पहले एनओसी की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। देवकली ने कहा कि वर्षों की मांग के बाद विद्यालय स्वीकृत हुआ था, लेकिन निर्माण रुकने से ग्रामीणों में निराशा है।

श्रमदान से स्वच्छता का संकल्प, मणिकर्णिकाघाट की गरिमा बढ़ाने का संदेश

एजेंसी

वाराणसी । उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में गंगा नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के बीच सोमवार को नगर निगम और नमामि गंगे की टीम ने मणिकर्णिकाघाट तीर्थ पर स्वच्छता सेवा अभियान में श्रमदान कर तीर्थ की गरिमा बढ़ाने का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान में शामिल गंगा सेवक राजेश शुक्ल ने बताया कि मणिकर्णिका तीर्थ पर श्रमदान करते समय ऐसा अनुभव होता है कि बाबा महादेव स्वयं सहायक हैं, यहां की आध्यात्मिक और दिव्य ऊर्जा का सीधा प्रभाव है। मणिकर्णिका घाट पर नगर निगम की टीम के साथ श्रमदान महाश्मशान की पवित्रता को बनाने में सहायक है। काशी का यह मणिकर्णिका घाट केवल अंतिम संस्कार का स्थल नहीं, बल्कि जीवन और मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहां सेवा करना अपने आप में सबसे बड़ा सत्कर्म है। हिन्दू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस महाश्मशान पर शिव की उपस्थिति है। स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं, इसलिए यहां श्रमदान या जनसेवा करने वाले को आंतरिक शक्ति और अलौकिक शांति की अनुभूति होती है, मानो महादेव हर पल मार्गदर्शन और सहायता कर रहे हों। इस पवित्र भूमि पर किया गया श्रम अहंकार को मिटाकर विशुद्ध भक्ति और समर्पण का भाव जगाता है और कर्म का एहसास कराता है। गंगा सेवक ने कहा कि मणिकर्णिका घाट की दिव्यता और यहां आने वाले श्रद्धालुओं में श्रमदान व सेवा का भाव इस पवित्र तीर्थ की गरिमा को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मणिकर्णिका घाट सनातन धर्म में केवल एक श्मशान या घाट नहीं है, बल्कि इसे महाश्मशान और मुक्ति का द्वार माना गया है। मणिकर्णिका घाट पर देश-विदेश से लोग आते हैं। यहां निरंतर होने वाले दाह-संस्कार के बीच स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। जब तक हर नागरिक और श्रद्धालु में श्रमदान (स्वैच्छिक सफाई और सेवा) का भाव नहीं जागेगा, तब तक इस स्थान की पवित्रता को बाहरी रूप से बनाए रखना कठिन है। गंगा सेवक ने कहा कि यह स्थान जीवन और मृत्यु के परम सत्य का बोध कराता है। यहां कचरा न फैलाना, घाट की मयार्दा का पालन करना और रीती-रिवाजों का सम्मान करना हर दर्शनार्थी का कर्तव्य है।

कानपुर बैराज में बढ़ा गंगा का जलस्तर, चेतावनी बिंदु के पार; प्रशासन अलर्ट पर

एजेंसी

कानपुर और आसपास के मैदानी इलाकों में मानसूनी गतिविधियों और ऊपरी क्षेत्रों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा नदी के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कानपुर बैराज पर गंगा का जलस्तर सोमवार को बढ़कर 114.230 मीटर के स्तर तक जा पहुंचा, जिसने प्रशासनिक स्तर पर चिंता और सतर्कता दोनों बढ़ा दी है। पिछले दिन यानी रविवार के जलस्तर की तुलना में सोमवार को नदी के पानी में 43 सेंटीमीटर की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के साथ ही नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु (114.000 मीटर) को पार करते हुए उससे 23 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि वर्तमान में जलस्तर खतरे के निशान (115.000 मीटर) से अभी भी 77 सेंटीमीटर नीचे बना हुआ है। जलस्तर में आई इस अचानक तेजी को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। कानपुर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन टीम और राजस्व अधिकारियों समेत तमाम संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि गंगा के जलस्तर में होने वाले हर छोटे-बड़े बदलाव पर 24 घंटे लगातार पैनी नजर रखी जाए और संवेदनशील तथा तटीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि तटीय इलाकों और कटान से प्रभावित होने वाले गांवों में नियमित रूप से निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि निचले इलाकों में रहने वाली आबादी को संभावित जलभराव या बाढ़ की स्थिति के प्रति पहले से सचेत किया जाए। यदि नदी का जलस्तर और बढ़ता है या किसी भी स्थान पर जलभराव अथवा कटान जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो राहत और बचाव कार्यों के तहत तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, आश्रय स्थलों की व्यवस्था, राहत सामग्री की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त रखने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। कानपुर बैराज के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र की बात करें तो वहां भी जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला देखा गया है। सोमवार को डाउनस्ट्रीम में जलस्तर बढ़कर 113.820 मीटर तक पहुंच गया। इससे एक दिन पहले, रविवार को डाउनस्ट्रीम का जलस्तर 113.530 मीटर पर दर्ज किया गया था। इस प्रकार डाउनस्ट्रीम में भी जलस्तर में 29 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा में बढ़ते पानी के दबाव को संतुलित करने और बैराज की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोमवार को कानपुर बैराज के गेट खोलकर 3,62,559 क्यूसेक पानी का भारी डिस्चार्ज दर्ज किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण डाउनस्ट्रीम के निचले और ग्रामीण इलाकों में जलस्तर का प्रभाव देखा जा रहा है। दूसरी ओर, उन्नाव जिले की सीमा से सटे शुक्लागंज क्षेत्र में भी गंगा के जलस्तर में भारी उछाल आया है। सोमवार को शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.790 मीटर दर्ज किया गया। रविवार को यहां

जलस्तर 112.290 मीटर था, यानी महज 24 घंटों के भीतर यहां नदी के पानी में 50 सेंटीमीटर (आधा मीटर) की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, शुक्लागंज में राहत की स्थिति यह है कि वर्तमान जलस्तर चेतावनी बिंदु 113.000 मीटर से 21 सेंटीमीटर नीचे बना हुआ है। यदि ऊपरी इलाकों से पानी की आवक इसी तरह बनी रहती है, तो जल्द ही शुक्लागंज में भी जलस्तर चेतावनी बिंदु को छू सकता है। बाढ़ नियंत्रण कार्यालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों और रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि दोनों स्थानों (कानपुर बैराज और शुक्लागंज) पर सोमवार शाम तक जलस्तर में धीरे-धीरे कमी का रुख (ट्रेंड) दर्ज किया गया है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की दौड़ में शैफाली, चरणी और अटापट्टू शामिल

दुबई (एजेंसी)। भारत की शैफाली वर्मा और श्री चराणी के साथ ही श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू को सितंबर महीने के आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की रैस में शामिल किया गया है। शैफाली वर्मा ने सितंबर के महीने में सात टी20 मैचों में कुल 360 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 72 और स्ट्राइक रेट 184.61 का प्रभावशाली रहा। बल्ले के साथ-साथ, शैफाली ने अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से भी योगदान दिया और पूरे महीने में छह महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। महिला एशिया कप में वह पांच पारियों में 236 रन बनाकर टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 64 और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 68 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जिससे भारत को रिकॉर्ड आठवां एशिया कप खिताब जीतने में मदद मिली। जापान में हुए एशियाई खेलों में भी शफाली ने तीन पारियों में 188 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में, उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों पर धमाकेदार 100 रन बनाकर अपने करियर का पहला टी20 शतक लगाया।

वहीं, भारत की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने पूरे सितंबर में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सात टी20 मैचों में कुल 18 विकेट लिए, जिसमें उनका गेंदबाजी औसत 4.83 और इकॉनमी रेट 3.30 रहा। महिला एशिया कप में चरणी ने भारत की खिताबी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां उन्होंने टूर्नामेंट में 12 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 4/20 का उनका स्पेल मैच विजेता रहा। एशियन गेम्स में भी चरणी ने अपनी दबदबा कायम रखा, जापान के खिलाफ 4/10, बांग्लादेश के खिलाफ 2/7 और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 2/13 के आंकड़े दर्ज करते हुए कुल आठ विकेट लिए। चरणी ने सितंबर के अंत में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया, जब वह आईसीसी महिला टी20 प्लेयर रैंकिंग्स में 817 रेटिंग अंकों के साथ महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाली गेंदबाज बन गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट्ट के 806 अंकों का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की।

इसके अलावा श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू भी इस अवॉर्ड की मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने सितंबर में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए सात टी20 में 226 रन बनाए, जिसमें उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 140.37 रहा। साथ ही, उन्होंने अपनी ऑफ-स्पिन से 14 विकेट भी हासिल किए,

उनका गेंदबाजी औसत 10.21 रहा।

इस प्रकार, शफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी, श्री चरणी की रिकॉर्डतोड़ गेंदबाजी, और चामरी अटापट्टू के दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की दौड़ को बेहद रोमांचक बना दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे ये अवॉर्ड मिलता है।

दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच बने गांगुली

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र को देखते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपना नया मुख्य कोच बनाया है। फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि कि गांगुली जैसे अनुभवी के कोच बनने से टीम आईपीएल 2027 सत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेगी। गांगुली पहली बार आईपीएल में मुख्य कोच के तौर पर नजर आयेंगे हालांकि वह पहले भी दिल्ली फ्रेंचाइजी में डायरेक्टर रहे थे। उन्हें हेमंग बदानी की जगह मुख्य कोच बनाया गया है। बदानी पिछले दो साल से दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच थे पर टीम कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पायी। बदानी के अलावा, टीम ने गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल, सहायक कोच इयान बेल और टीम डायरेक्टर वेणुगोपाल राव को भी हटाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि गांगुली अपनी टीम को अपनी रणनीतिक सोच के अनुरूप ढालने के लिए अपना खुद का सहायोगी स्टाफ बनाना चाहते हैं, जिसके चलते ये बड़े बदलाव किए गए हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले दो आईपीएल सीज़न बेहद निराशाजनक रहे थे। टीम आईपीएल 2025 में पांचवें और 2026 में छठे स्थान पर रही थी, दोनों बार प्लेऑफ में जगह बनाने में विफल रही। ऐसे में, गांगुली जैसे अनुभवी और सफल लीडर की नियुक्ति को टीम के भाग्य को पलटने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गांगुली साल 2019 से ही फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने पुरुष और महिला दोनों टीमों में डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी।

कोचिंग स्टाफ में गांगुली को पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह का साथ मिल सकता है, हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हेड कोच के तौर पर गांगुली का यह पहला आईपीएल अनुभव होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी लीग एसए 20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच रहते हुए वे अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में सफल रहे थे, जो उनके कोचिंग कौशल का प्रमाण है।

गांगुली ने इस नई भूमिका को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हेड कोच का पद संभालने को उत्साहित हूं। दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी मेरे दिल के बहुत करीब रही है और पिछले सालों इसके साथ मेरे रिश्ते और मजबूत हुए हैं। उन्होंने एक मजबूत और निडर टीम बनाने का दावा किया, जो मैदान पर अपने प्रदर्शन से विरोधियों को चुनौती दे सके।

गांगुली दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अक्षर पटेल और केएल राहुल जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ काम करते दिखेंगे। इस सीज़न से पहले टीम में एक और बड़ा बदलाव ऋषभ पंत की वापसी के रूप में हुआ है। पंत ने दो साल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की थी, लेकिन आईपीएल 2026 के समापन के बाद दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए एक बड़े ट्रेड के तहत वे दिल्ली लौटे।

भुवनेश्वर हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान बने

मुम्बई। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भुवनेश्वर के अलावा स्पिन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश राणा को भी टीम में शामिल किया गया है। भूवी के नाम से लोकप्रिय भुवनेश्वर ने भारतीय टीम के लिए पिछला मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था। हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए भुवनेश्वर को भारतीय टीम की कप्तानी दी गयी है। टीम में भुवनेश्वर के अलावा आईपीएल से भी कुछ खिलाड़ियों को अवसर मिला है। हांगकांग सिक्स सीरीज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी। वहीं टूर्नामेंट का समापन 01 नवंबर को होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों को 4 पूल्स में बांटा गया है। पूल-ए में- हांगकांग चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। वहीं पूल-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड है। पूल-सी में- भारत, पाकिस्तान और यूएई है। पूल-डी में- दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और ओमान है।

चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट : प्रशंसक की आंख में शॉट लगाने से मेदवेदेव हुए अयोग्य, जोकोविच फाइनल में पहुंचे

बीजिंग। यहां खेले गये चीन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव का एक शॉट सीधे एक प्रशंसक की आंख में लगने से अयोग्य होकर बाहर हो गये। इससे सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सीधे टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। यह घटना जब हुई तब मेदवेदेव सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच से 7-5, 5-3 से पीछे चल रहे थे। रूसी खिलाड़ी ने गुस्से में एक शॉट मारा जो सीधे स्टैंड्स में बैठे एक दर्शक की आंख में लग गया। इस अप्रत्याशित हादसे से सभी लोग सकते में पड़ गये। ये हादसा तब हुआ जब मेदवेदेव एक अंक हारने से निराशा थे। उन्होंने बैकबोर्ड से टकराकर वापस आ रही गेंद पर इतनी तेजी से शॉट लगाया कि गेंद सामने बैठे एक दर्शक की बाईं आंख में जा लगी। दर्शक तुरंत अपनी आंख पकड़कर दर्द से कराह उठा, जिससे खेल कुछ समय के लिए रुक गया। घायल दर्शक को तुरंत स्टेडियम कर्मचारियों की मदद से उपचार के लिए बाहर ले जाया गया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, अंपायर मोहम्मद लाहयानी और एटीपी अधिकारियों ने मेदवेदेव को मैच से आगे खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। मेदवेदेव ने घटना के बाद नेट के पास आकर जोकोविच से हाथ मिलाया और कहा कि उन्हें इस घटना का बेहद दुख है और वह दर्शक से भी माफी मांगना चाहते हैं। वहीं जोकोविच ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मेदवेदेव के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही कहा कि साल 2020 यूएस ओपन में उन्हें भी इसी तरह एक लाइन जज को अनजाने में गेंद लगने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। जोकोविच ने कहा, मुझे उम्मीद है कि उस व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई होगी। दूसरी ओर मुझे डेनिलमेदवेदेव के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसी बड़े मैच में अयोग्य घोषित होने पर कैसा महसूस होता है। मुझे भरोसा है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। ये एक मानवीय भूल थी।

पाक सरकार पर बरसे शास्त्री, बोले इमरान खान को तत्काल रिहा किया जाये

मुम्बई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि पाक टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान को तत्काल जेल से रिहा किया जाये। शास्त्री ने पाकिस्तान सरकार द्वारा इमरान के साथ किए जा रहे व्यवहार को अमानवीय बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और कहा कि देश को पहला एकदिवसय विश्व कप दिलाने वाले खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के साथ जो कर रही है, वह किसी भी मायने में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शास्त्री ने इस स्थिति पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, लेकिन उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, वह देखना वास्तव में हैरान करने वाला है। कोई भी किसी इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता। इमरान के साथ इस समय जो हो रहा है, वह उसके बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा, बल्कि पूरे विश्व में ऐसे कई क्रिकेटर होंगे जो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे।

बिग बॉस से बाहर आते ही छलका ईशा रिखी का दर्द

सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में आए दिन कुछ न कुछ नया और धमाकेदार देखने को मिल रहा है। इसमें कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से दो प्रतियोगी रोहैद खान और ईशा रिखी अभी तक बाहर हो गए हैं। तीन हफ्ते घर में रहने के बाद अब बादशाह की एक्स वाइफ ने शो से बाहर आते ही सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया है। ईशा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए पोस्ट में लिखा, 'बिग बॉस के घर के अंदर बिताए तीन हफ्ते... तीन हफ्ते जिनमें मैंने बहुत सारी भावनाएं, अनुभव, चुनौतियां, हंसी, आंसू और ऐसी यादें जी हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। वापस आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है।' ईशा ने पोस्ट में आगे लिखा, 'उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, जो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे चीयर किया। उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हर राय, हर मैसेज और इस सफर का किसी भी तरह हिस्सा रहे हर एक इंसान के लिए आभारी हूं।' ईशा ने आगे बताया, 'पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए आसान नहीं थे। मेरे कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, कुछ ऐसे पल आए जब मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह पाई और कुछ मौकों पर शायद मैं वैसा नहीं दिख पाई, जैसा मैं खुद को दिखाना चाहती थी। मुझे पता है कि शायद मैंने आपमें से कुछ लोगों को निराश किया होगा और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे सच में अफसोस है। मैं अभी भी इन सब चीजों को समझ रही हूं, खुद को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रही हूं और इस पूरे अनुभव से सीख रही हूं।'

ईशा ने क्यों कहा शुक्रिया

अपनी बात खत्म करते हुए ईशा ने लास्ट में लिखा, 'लेकिन एक बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, वह यह है कि मैंने आपका प्यार महसूस किया। भले ही मैं खुद ज्यादा कुछ जाहिर नहीं कर पाई, लेकिन यह बात मेरे लिए शब्दों में बयां करने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। मेरे साथ खड़े रहने, मुझे समझने और लगातार मेरा सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सच में, बहुत-बहुत आभारी हूं।'

कौन हैं ईशा रिखी

ईशा रिखी पंजाबी अभिनेत्री हैं। उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टा दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास' और 'मिंडो तसीलदारनी' जैसी कई फिल्मों में दिखाई दीं। इस साल की शुरुआत में ईशा रैपर-सिंगर बादशाह से शादी करने को लेकर सुर्खियों में आई थीं। हालांकि, दोनों का रिश्ता पांच महीने ही चला और दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अपने अलग होने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद ईशा ने 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लिया था और अब वह वहां से भी बाहर हो गई हैं।

ब्रेकअप के बाद जिंदगी बदल गई है

अभिनेत्री उदिति सिंह इस समय रियलिटी शो 'बिग बॉस-20' में नजर आ रही हैं। शो के दौरान उदिति ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड और अभिनेता करण वाही के साथ रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की। उदिति ने बताया कि कैसे 'कोविड-19' लॉकडाउन के दौरान उनका रिश्ता खराब होने लगा था। साथी कंटेस्टेंट स्काउट से बात करते हुए उदिति ने कहा कि अलग होने के बाद उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह बदल गई। उदिति ने कहा, 'ब्रेकअप के बाद मेरे लिए यह एक तरह से वरदान साबित हुआ। क्योंकि उसके बाद मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी लाइफ, सब कुछ बदल गया था।' उन्होंने आगे बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने और उनके एक्स-पार्टनर ने एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम 'नोआ' है। उदिति सिंह ने कहा, 'हमने लॉकडाउन में साथ में नोआ नाम का गोल्डन रिट्रीवर लिया था, तो उसी को लेकर हमारे बीच काफी झगड़े शुरू हो गए थे। उस वक्त कोविड भी था, तो हम दोनों पर सफाई का काफी काम रहता था। मेरा सफाई करने का तरीका अलग था और उसका अलग। फिर वह इस बात को लेकर थोड़ा डॉमिनेट भी करता था और कहता था, 'तुम्हें नहीं आता।' क्योंकि वह उम्र को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था, उसके लिए हर चीज ऐसी थी कि 'तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें ये-वो नहीं आता।', 'तुम नोआ को नहीं संभाल पाओगी।' तो मुझे लगता था कि मेरा पार्टनर बहुत डीमोटिवेट करने वाला है।' उदिति ने आगे कहा, 'ऐसा ही होता है, जब दो लोगों का एक होना नहीं लिखा होता है, तो बात-बात पर लड़ाई होती है और जब एक होना लिखा होता है, तब सब कुछ अच्छा होता है।' उदिति का यह बयान 'बिग बॉस 20' के घर में करण के साथ अपने रिश्ते को लेकर पहले की गई बातों के बाद आया है। दोनों के रिश्ते के बारे में साल 2019-20 के आसपास सभी को पता था, उस वक्त करण ने उदिति के साथ तस्वीरें भी शेयर की थीं। बताया जाता है कि उनका रिश्ता काफी सीरियस था। उदिति ने पहले घरवालों को बताया था कि दोनों करीब ढाई साल तक साथ रहे थे और शादी तक की बात भी हुई थी।

लस्ट स्टोरीज 3 में सायरा बनकर छाईं अदिति राव हैदरी

अदिति राव हैदरी इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई 'लस्ट स्टोरीज 3' को मिल रहे प्यार और सराहना का आनंद ले रही हैं। फिल्म में अभिनेत्री ने अपने समय से काफी आगे का किरदार निभाया है। सायरा के किरदार में अदिति न सिर्फ वासना, चाहत और महिला सुख की भावनाओं को बखूबी पर्दे पर उतारती हैं, बल्कि पिता और बेटी के रिश्ते की खूबसूरती को भी भावनात्मक रूप से दर्शाती हैं। अभिनेत्री ने अपने वास्तविक जीवन की एक याद को साझा करते हुए बताया कि गजराज राव के साथ इस रिश्ते को पर्दे पर निभाना उनके लिए बेहद निजी और भावुक अनुभव था। फिल्म में गजराज राव उनके ऑन-स्क्रीन ससुर के किरदार में नजर आते हैं। अदिति बताती हैं, जो कुछ कागज पर लिखा गया था, वह बहुत खूबसूरत था। लेकिन जाहिर तौर पर जब निर्देशक अपनी समझ और नजरिए को उसमें जोड़ते हैं और आपके सामने गजराज राव जैसे अभिनेता होते हैं, तो मेरे लिए यह रिश्ता बहुत ही कोमल और भावुक बन गया। कहानी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह उस परिवार की प्रगतिशील सोच थी, जहां ससुर इस लड़की के साथ खड़े होते हैं और उसके सहयोगी बनते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि हर कोई कहता है, 'ये तो हमारे घर की बच्ची है, ये तो हमारी बेटी है।' लेकिन 1987 के दौर में एक लड़की का अपने ससुर में एक ऐसे व्यक्ति को पाना, जिसके साथ वह अपने मन की बात साझा कर सके, मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, कल ही यह बात मेरे मन में आई कि यह लगभग एक आदर्श प्रेम कहानी जैसी है, जहां इच्छाएं अधूरी हैं, लेकिन वे सभी बहुत सारे प्यार के साथ अधूरी हैं। वह आगे कहती हैं, एक लड़की का अपनी कला के जरिए अपना साहस तलाश पाना, मुझे यह भी बेहद अद्भुत लगता है। पति और ससुर, दोनों का इस सफर में उसका साथ देना बहुत खूबसूरत है, चाहे वह नृत्य हो, संगीत हो, लेखन हो, कविता हो या साहित्य। लड़कियों के लिए और हम सभी के लिए यही हमारी आवाज है। यह हमें अपने होने का एक ऐसा एहसास देता है, जो पूरी तरह हमारा है। अदिति ने कहा, मुझे जिंदगी में यह बात हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है। इसलिए मुझे वह सीन बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें बहुत कोमलता थी। मेरे पिता का निधन उस समय हुआ जब उन्हें अभी और जीना चाहिए था। वह बीमार थे। इसलिए मेरे लिए माता-पिता और बच्चे के बीच का कोई भी सीन बहुत... बहुत ज्यादा मायने रखता है। वह मेरे लिए बेहद भावुक था। वह बहुत खूबसूरत था।

चूक गया। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप चौंपियन बनाया। क्लब स्तर पर खलत रहग। वह फिलहाल इटर

एयरपोर्ट के लेबर कैंप में आग, 33 कमरे जले

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में बने लेबर कैंप में मंगलवार सुबह 6-30 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में तीन मंजिला बिल्डिंग जल गई। धुआं 2 किमी दूर तक दिखाई दिया। तुरंत फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंचीं। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दो मजदूर घायल हुए हैं। एक आग की चपेट में आने से झुलस गया, जबकि दूसरा दूसरी मंजिल से कूदने की वजह से चोटिल हुआ। जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह टर्मिनल से करीब 250-300 मीटर दूर है। इसे मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी तौर पर पीवीसी यानी प्लास्टिक से बनाया गया था। यही वजह थी कि आग बहुत तेजी से फैली। हालांकि, इस हादसे से विमानों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट परिसर की इस बिल्डिंग में 33 छोटे कमरे हैं। इसमें करीब 300 मजदूर रहते हैं। वे परिसर में एक होटल का निर्माण कर रहे हैं।

अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल युवक पकड़ाया, भारी मात्रा में हथियार बरामद

इंफाल(एजेंसी)। मणिपुर के इंफाल पूर्व जिले में अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल व्यक्ति को सरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने सोमवार को थम्बालनू बाजार में अभियान चलाया और संदिग्ध को पकड़ा। वह अवैध हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की खरीद और बिक्री में शामिल है। जांच में पता चला कि आरोपी ने जुलाई में दो महिलाओं के जरिए 10,000 रुपए में एक व्यक्ति को एक हथगोला मुहैया कराया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अलग अभियान में सुरक्षा बलों ने सोमवार को चुराचांदपुर जिले के कुकिमुन गांव में बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किए। पुलिस के मुताबिक फ्रदो 9 एमएम कार्बाइन मशीन गन, तीन 9 एमएम पिस्तौल, सात सिंगल बैरल बोल्ट-एक्शन राइफल, एक हैंड ग्रेनेड, एक मोर्टार बम और दो देसी मोर्टार बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि जब्त हथियार और गोला-बारूद जिले के हेंगलेप पुलिस थाने को सौंप दिए हैं। बता दें मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से सुरक्षा बल मणिपुर के सभी जिलों के सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अभियान चला रहे हैं। घाटी में रहने वाले मेइती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच मई 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष में कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

कर्नाटक में बीयर की बढ़ती खपत से डीके सरकार की ताबड़तोड़ कमाई

बेंगलुरु(एजेंसी)। शराब मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बावजूद, राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। इसी कड़ी में, कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार ने हाल ही में आबकारी विभाग से जबरदस्त कमाई दर्ज की है। जुलाई से सितंबर 2026 के दूसरे क्वार्टर के दौरान, राज्य को 11,595.88 करोड़ का राजस्व मिला, जो पिछले साल इसी अवधि के 10,303.94 करोड़ रुपये से 12.54 प्रतिशत अधिक है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का मुख्य कारण बीयर और इंडियन मेड लिकर (आईएमएल) की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी रही है। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में बीयर की बिक्री में अप्रत्याशित उछाल दिखाई दिया। जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान 126.68 लाख केस बॉक्स बीयर बेची गई, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 84.63 लाख केस बॉक्स था। यह सालाना आधार पर करीब 49.69 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दिखाता है। बीयर की बढ़ती लोकप्रियता का सीधा असर सरकार की आय पर पड़ा, जिससे आबकारी राजस्व 1,234.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,463.07 करोड़ रुपये हो गया, जो 18.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

नई दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन से पहले पुलिस नोटिस पर हंगामा, दिपके ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि पुलिस दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले पार्टी के प्रस्तावित आंदोलन से पहले कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उन पर दबाव बना रही है। दिपके ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधकर दावा किया कि एक देश, एक चुनाव सिर्फ़ एक नारा है और इसका असली मक़सद एक देश, एक राजनीतिक पार्टी स्थापित करना है। सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करने का आह्वान किया है। छत्रपति संभाजीनगर में प्रेसवार्ता को संबोधित कर दिपके ने बताया कि चंद्रपुर पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनसे दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल न होने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के दिल्ली यात्रा खर्च के स्रोत के बारे में भी पूछताछ की। दिपके ने महाराष्ट्र पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस फ़ोर्स बताकर दुख व्यक्त किया कि चंद्रपुर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है।

ब्राजील चुनाव: पहले दौर में लूला से आगे रहे फ्लावियो बोल्सोनारो, 25 अक्टूबर को होगा दूसरा मुकाबला

ब्रासीलिया, एजेंसी। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 98.81 प्रतिशत वोटों की गिनती पूरी होने तक बोल्सोनारो को 47.24 प्रतिशत वोट मिले, जबकि लूला को 44.91 प्रतिशत वोट हासिल हुए। पहले दौर में दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से आगे रहे। हालांकि, वह सीधे जीत के लिए जरूरी 50 प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर सके। अब दोनों उम्मीदवारों के बीच 25 अक्टूबर को दूसरे दौर का मुकाबला होगा। ब्राजील की चुनाव व्यवस्था के मुताबिक, पहले दौर में जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है। दोनों में से कोई भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका, इसलिए अब दोनों दूसरे दौर में आमने-सामने होंगे। पहला दौर फ्लावियो बोल्सोनारो के लिए मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। वह ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। पूर्व दक्षिणपंथी नेता जायर बोल्सोनारो पिछले चुनाव के नतीजे को सैन्य तख्तापलट के जरिए पलटने की नाकाम कोशिश की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 27 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। पहले दौर का मुकाबला शुरू से ही करीबी रहने की उम्मीद थी। हालांकि, चुनाव प्रचार के दौरान ओपिनियन पोल में लूला मामूली बढ़त बनाए हुए थे। इसके बावजूद फ्लावियो बोल्सोनारो का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा और इससे दूसरे दौर से पहले ब्राजील की राजनीतिक तस्वीर काफी बदल गई है। पहले दौर के नतीजे बोल्सोनारो के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे दौर में जगह नहीं बना पाने वाले कई उम्मीदवार दक्षिणपंथी खेमे से थे। अगर बोल्सोनारो इन उम्मीदवारों के समर्थकों का वोट अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहते हैं, तो 25 अक्टूबर के मुकाबले में यह अहम साबित हो सकता है।

वहीं, लूला अब अपने मौजूदा वोटरों का समर्थन बनाए रखने के साथ-साथ उन लोगों को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने पहले दौर में बाहर हो चुके उम्मीदवारों को वोट दिया था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दक्षिणपंथी खेमे को ब्राजील की सत्ता में आने से रोकने की होगी। ब्राजील के चुनाव पर पूरे लैटिन अमेरिका की नजर है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के कई देशों में दक्षिणपंथी नेता राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनमें से कई नेताओं के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ करीबी राजनीतिक रिश्ते हैं। यही वजह है कि ब्राजील में दूसरे दौर का चुनाव सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। 25 अक्टूबर को लूला और फ्लावियो बोल्सोनारो के बीच होने वाला मुकाबला तय करेगा कि ब्राजील में वामपंथी नेतृत्व जारी रहेगा या लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में बढ़ते दक्षिणपंथी रुझान के बीच देश की सत्ता भी दक्षिणपंथ की ओर जाएगी।

ट्रंप के सामने खड़े होने का लूला को फायदा : कभी बेहद लोकप्रिय रहे लूला के तीसरे कार्यकाल में उनकी लोकप्रियता और समर्थन में काफी गिरावट आई है। लेकिन अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े होने से उन्हें फायदा मिला है। उनके पास अब भी समर्थकों का एक मजबूत आधार है। ये समर्थक मानते हैं कि उनकी सामाजिक नीतियों से लाखों ब्राजीलियाई लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। मौजूदा राष्ट्रपति लूला ने ब्राजील के चुनाव में अमेरिकी दखल के खतरे की बात कई बार कही है। ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील से होने वाले सामान के निर्यात पर भारी टैरिफ लगाया है। उसने ब्राजील के राजदूत का वीजा भी रद्द किया है।

अमेरिकी प्रशासन ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर भी प्रतिबंध लगाया है। यही जज जेर बोल्सोनारो की जांच की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी जांच के बाद बोल्सोनारो को सजा सुनाई गई। रविवार को मतदान करने के बाद लूला ने पत्रकारों से कहा कि दोबारा चुने जाने पर उन्हें 'हमने जो किया है, उसका दोगुना करना होगा'। उन्होंने पहले दौर में ही जीत हासिल करने का भरोसा भी जताया।

लेकिन लूला के सामने कड़ी चुनौती है। देश में लोगों के लिए चीजें खरीदना महंगा हो रहा है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार का एक मामला भी सामने आया है। इसमें वही जज घिरे हैं, जिन्होंने जेर बोल्सोनारो के खिलाफ जांच का नेतृत्व किया था।

साओ पाउलो की इंस्पर यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कार्लोस मेलो ने कहा, कुछ हफ्ते पहले लूला के अभियान से जुड़े कई लोगों को इतनी मुश्किल चुनावी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। अब उनके लिए साफ है कि मौजूदा चुनाव एक कठिन लड़ाई है।

रूस के ड्रोन हमलों के बीच कीव पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज: एक अरब यूरो की मदद का एलान

कीव, एजेंसी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रविवार को कहा कि जर्मनी को डराकर यूक्रेन के समर्थन से पीछे नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कीव की यात्रा के दौरान यूक्रेन के लिए 1 अरब यूरो यानी करीब 1.1 अरब डॉलर की अतिरिक्त सैन्य मदद का एलान किया। मर्ज की यह यात्रा ऐसे समय हुई, जब रूस ने कीव पर ड्रोन हमले किए। मर्ज और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने चार साल से जारी युद्ध में मारे गए सैनिकों के स्मारक का दौरा किया। इस दौरान यूक्रेन की राजधानी में बार-बार हवाई हमले के सायरन और धमाकों की आवाज सुनाई दी। दोनों नेता विज्ञान अकादमी भी गए। पिछले हफ्ते यहां हुए ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हुई थी। रूस ने हाल के हफ्तों में कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। इन हमलों में दूरसंचार, बिजली और परिवहन ढांचे के साथ-साथ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्ज ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र की मरम्मत के लिए 350 मिलियन यूरो की मदद का भी एलान किया। मर्ज ने कहा कि जर्मनी यूक्रेन का सबसे मजबूत समर्थक बना हुआ है।

मर्ज ने कहा, हम ऐसा सिर्फ यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। हम यह अपने हित में भी कर रहे हैं, क्योंकि यह यूरोप की सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि रूस साइबर हमले और दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। ये हमले यूरोप की लोकतांत्रिक व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं। मर्ज ने कहा, यह दिखाता है कि हम डरने वाले नहीं हैं। रूस ने हाइब्रिड युद्ध के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रूस का कहना है कि ये आरोप रूस विरोधी उन्माद का नतीजा हैं। अधिकारियों ने बताया कि मर्ज के साथ जर्मनी की कंपनियों के अधिकारी भी यूक्रेन गए थे। इन अधिकारियों ने यूक्रेन सरकार और कारोबारों के साथ 16 समझौते किए। इन समझौतों की कुल कीमत करीब 6.5 अरब यूरो है। इनमें यूक्रेन ने जर्मनी की कंपनी डील डिफेंस के साथ आईआरआईएस-टी एयर डिफेंस मिसाइलों की आपूर्ति का समझौता किया। इसके अलावा, हेंसोल्ड्ट के साथ रडार उपकरण और क्वांटम सिस्टम्स के साथ जेट ड्रोन इंटरसेप्टर की आपूर्ति का समझौता हुआ। जेलेंस्की ने क्वांटम सिस्टम्स की ओर से बनाए गए नए जेट ड्रोन इंटरसेप्टर की तारीफ की। इसका नाम एसपीवाईएस बताया गया है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे उम्मीद के मुताबिक अच्छे रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और जर्मनी एक बड़े रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। उन्होंने पहले कहा था कि इस समझौते में ड्रोन, मिसाइल और उनसे जुड़े सॉफ्टवेयर का उत्पादन शामिल होगा। गर्मियों से रूस हर दिन यूक्रेन के नागरिक और सैन्य ढांचे को निशाना बना रहा है। इन हमलों में दर्जनों तेज रफ्तार जेट इंजन वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

जापान में बवाल: ओकिनावा में महिला की हत्या के आरोप में अमेरिकी मरीन गिरफ्तार

टोक्यो , एजेंसी। जापान के ओकिनावा में एक स्थानीय महिला की कथित हत्या और लूट के मामले में एक अमेरिकी मरीन को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद जापान में खासकर ओकिनावा के लोगों में भारी नाराजगी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी को लेकर पहले से असंतोष के बीच इस घटना ने विवाद को और बढ़ा दिया है। ओकिनावा प्रीफेक्चरल पुलिस के मुताबिक, 20 वर्षीय अमेरिकी मरीन को शनिवार तड़के नाहा शहर के एक होटल में 39 वर्षीय महिला की हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया। आरोपी फुतेंमा एयर स्टेशन पर तैनात है। उस पर महिला का बटुआ और बैकपैक ले जाने का भी आरोप है। जापानी समाचार एजेंसी क्योदो के अनुसार, महिला का शव होटल के कमरे में मिला। शुरुआती जांच में आशंका है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला के साथ होटल में प्रवेश करता दिखाई दिया। कुछ समय बाद वह अकेले होटल से बाहर निकला। पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात नाहा के मनोरंजन क्षेत्र में आरोपी को अकेले घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ओकिनावा के नवनिर्वाचित गवर्नर जेंता कोजा ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस घटना से ओकिनावा के लोगों को बड़ा झटका लगा है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास रहने वाले लोगों में डर बढ़ गया है। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के अनुशासन और प्रशिक्षण पर भी सवाल उठाए। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने भी घटना को बेहद दुखद और गंभीर अपराध बताया। उन्होंने कहा कि जापान सरकार ने अमेरिकी पक्ष के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही जांच में पूरा सहयोग देने, अमेरिकी सैनिकों पर कड़ा अनुशासन लागू करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने की मांग की गई है। विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने अमेरिकी राजदूत जॉर्ज ग्लास को तलब कर घटना पर जापान का आक्रोश जताया।

ट्रम्प के कामकाज से 70% अमेरिकी संतुष्ट नहीं: मिडटर्म चुनाव हार सकते हैं ट्रम्प

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी में बगावत के संकेत दिखने लगे हैं। ट्रम्प की लोकप्रियता घट रही है। पार्टी नेताओं को डर है कि मिडटर्म चुनाव में ट्रम्प का साथ उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले कई रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रम्प से दूरी बना रहे हैं। कुछ ने अपनी चुनावी वेबसाइट से ट्रम्प और उनके 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे का जिक्र हटा दिया है। कुछ नेता उनके साथ मंच साझा करने से भी बच रहे हैं।

एपी-एनओआरसी सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 30% अमेरिकी ट्रम्प के कामकाज से खुश हैं। अर्थव्यवस्था पर उनकी अप्रूवल रेटिंग 26% है। महंगाई से निपटने के मामले में यह सिर्फ 17% है। 65% से ज्यादा अमेरिकी बढ़ती कीमतों के लिए ट्रम्प की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं।

ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ कई रिपब्लिकंस : आयोवा से सांसद और सीनेट उम्मीदवार एश्ले हिंसन और मिशिगन के सीनेट उम्मीदवार माइक रोजर्स ने ईरान युद्ध जल्द खत्म करने की मांग की है। दोनों पहले ट्रम्प की सैन्य कार्रवाई के समर्थक थे। आयोवा के सांसद जैक नन और मैरियानेट मिलर-मीक्स ने ट्रम्प की युद्ध शक्तियां सीमित करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ वोट किया। फ्लोरिडा की सांसद मारिया ने ट्रम्प की सख्त इमिग्रेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। कई उम्मीदवारों ने कहा है कि वे ट्रम्प का प्रचार नहीं चाहते। रिपब्लिकन उम्मीदवारों की बेचैनी के पीछे सबसे बड़ा कारण अर्थव्यवस्था है। 24 से 28 सितंबर के एपी-एनओआरसी सर्वे में केवल 17% अमेरिकियों ने कहा कि वे ट्रम्प के जीवनयापन की लागत संभालने के तरीके से संतुष्ट हैं। अर्थव्यवस्था पर उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 26% रही, जबकि कुल कामकाज से 10 में केवल 3 अमेरिकी ही संतुष्ट हैं। 65% से ज्यादा अमेरिकी लगातार ऊंची कीमतों के लिए सीधे ट्रम्प की नीतियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। 64% का कहना है कि टैरिफ के मामले में ट्रम्प जरूरत से ज्यादा आगे चले गए। वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए दिक्कत यह है कि वे महंगाई के खिलाफ प्रचार तो करना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति की आर्थिक नीतियों से खुद को पूरी तरह अलग भी नहीं कर सकते। ट्रम्प से दूरी बनाने वालों की सूची में गवर्नर पद पर लड़ रहे विस्कॉन्सिन के टॉम टिफनी, एरिजोना के एली क्रेन और जॉर्जिया के रिक जैक्सन जैसे नाम शामिल हैं। सांसदों से जुड़े चेहरों में जॉर्जिया की मार्जरी टेलर, केंटकी के जेम्स कोमर, ओहायो के जिम जॉर्डन और साउथ कैरोलिना की नैन्सी मेस हैं। ये लंबे समय तक ट्रम्प के समर्थक रहे हैं। ओहायो गवर्नर चुनाव में भारतवंशी विवेक रामास्वामी के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। ट्रम्प ने 2024 में यह राज्य 11 पॉइंट से जीता था, लेकिन 24 से 27 सितंबर के मैरिस्ट सर्वे में डेमोक्रेट एमी एक्टन 50% समर्थन के साथ रामास्वामी से 44% से आगे हैं। इसी सर्वे में ट्रम्प का अप्रूवल 42% रहा। 41% वोटर्स ने कहा कि चुनाव में उनका वोट मुख्य रूप से ट्रम्प के खिलाफ होगा।

ज्ञानेश से जुड़े 2006 के मामले की केरल सरकार कराएगी जांच... समय को लेकर उठे सवाल

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल सरकार ने करीब दो दशक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। केरल सरकार में गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 4 अक्टूबर को विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) को जांच के निर्देश दिए। मामला 2006 में कुमार के केरल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव रहते केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएसटीपी) में कथित अनियमितताओं और मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा है।
केएसटीपी के तहत राज्य की प्रमुख सड़कों के उन्नयन का काम हो रहा था। एमसी रोड के एक हिस्से के विकास का करीब 215 करोड़ रुपये का ठेका इंडो-मलेशियन संयुक्त उपक्रम पाटिल-बीईएल को मिला था। परियोजना में जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण काम प्रभावित हुआ और भुगतान को लेकर ठेकेदार तथा पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बीच विवाद सामने आया। रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 17 करोड़ रुपये के भुगतान रोक दिए गए थे। इस दौरान पाटिल-बीईएल के केरल में प्रोजेक्ट मैनेजर ली सी बीन ने 2006 में मलेशिया में आत्महत्या कर ली। रिपोर्टों के अनुसार, उनके कथित सुसाइड नोट में तत्कालीन पाटिल-बीईएल सचिव ज्ञानेश कुमार सहित कुछ अधिकारियों के नाम थे। नोट में भुगतान जारी करने में कथित बाधाओं और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। हालांकि, ये आरोप उस समय सामने आए थे और मौजूदा जांच का उद्देश्य उनकी सत्यता तथा पूरे मामले की परिस्थितियों की फिर पड़ताल करना है।
ली की मौत के बाद 2006 में विजिलेंस जांच शुरू की गई थी। तब ज्ञानेश कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव पद से हटाया गया और बाद में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। पुरानी जांच आगे नहीं बढ़ सकी। अब सरकार ने शिकायत के आधार पर उस मामले को फिर खोलने का फैसला किया है। विजिलेंस विभाग 2005-06 के पीडब्ल्यूडी रिकॉर्ड और पहले हुई जांच से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा है।
मामले को फिर खोलने का राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। यह कदम तब आया है जब ज्ञानेश कुमार को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्षी दलों का विरोध जारी है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़े फैसलों को आयोग द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया बताया है। केरल सरकार का कहना है कि कानूनी राय लेने के बाद जांच में कोई कानूनी बाधा नहीं पाई गई। वहीं, बीजेपी ने दो दशक पुराने मामले को फिर खोलने के समय और पिछली सरकारों में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल ज्ञानेश कुमार की ओर से नई विजिलेंस जांच पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच के जरिए अब पुराने आरोपों, परियोजना से जुड़े रिकॉर्ड और पहले की जांच की स्थिति की नए सिरे से पड़ताल की जाएगी।

छलका सीएम यादव का दर्द बोले- बहुत महंगी पड़ गई लाडली बहना

भोपाल, एजेंसी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को बहुत खर्चीली बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के समय उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आर्थिक बोझ इतना भारी होगा। राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही, जिस पर राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के रवींद्र भवन में बुंदेली समागम-2026 कार्यक्रम में छतरपुर की बुंदेली कंटेंट क्रिएटर बिन्नू रानी के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब बिन्नू ने बेटियों के लिए सरकार की भावी योजनाओं के बारे में पूछा, तो सीएम यादव ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री बनते ही इतनी भारी मार पड़ती है, लाडली बहना योजना बहुत खर्चीली साबित हुई।
उन्होंने मजाकिया लहजे में आगे कहा, बेटा ये अंदर की बात हैज मुझे क्या पता था कि मुख्यमंत्री बनते ही ऐसी मार पड़ती है। मोहन यादव के इस बयान पर विपक्षी दल कांग्रेस ने तुरंत निशाना साधा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता उमंग सिंघर ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव से पहले लाडली और सत्ता में आते ही परेशानी। यही है भाजपा का महिला सम्मान। कांग्रेस ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये का आरोप लगाया, जिसमें चुनावी लाभ के लिए योजनाओं का वादा किया जाता है, लेकिन सत्ता में आने पर उनके वित्तीय बोझ पर चिंता व्यक्त की जाती है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि बहनों के मामले में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने लाडली बहना योजना के सफर का जिक्र किया, जो 1000 रुपये से शुरू हुआ था और अब 1500 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने बिन्नू रानी से कहा, चिंता मत करो। अभी तुम लाडली बहना योजना के लिए योग्य नहीं हो। थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हें यह योजना दे देंगे। यह टिप्पणी उनके हल्के-फुल्के अंदाज को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर भी सीएम के बयान पर खूब चर्चा हुई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे बच्ची के साथ किया गया एक मजाक बताया और कांग्रेस पर चुनाव नजदीक आने के कारण अनावश्यक रूप से हमलावर होने का आरोप लगाया। वहीं, कुछ अन्य लोगों ने कहा कि सीएम यादव के मुंह से सच्चाई निकल आई है और यह योजना मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है।

लोकसभा चुनाव-2029 की बहस के बीच टीवीके इंडिया गठबंधन में शामिल !

विजय की पीएम उम्मीदवारी पर संशय

चेन्नई, एजेंसी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी, तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके), औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश में लोकसभा चुनाव 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर गहन बहस जारी है। हालांकि, संसद में फिलहाल टीवीके का कोई प्रतिनिधित्व न होने के कारण, इस गठबंधन का प्रभाव दिल्ली तक अभी सीमित है। कांग्रेस के तमिलनाडु प्रमुख बी मणिकम टैगोर ने टीवीके के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में विपक्षी मोर्चा और अधिक मजबूत होगा, जिससे आरएसएस-भाजपा सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक मुकाबला और प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकेगा।
विजय के इस निर्णय को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें हैं। एक पहलू इसे राजनीतिक मजबूरी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, पिछले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था, लेकिन उसे केवल 108 सीटें ही मिली थीं। सरकार बनाने के लिए उसे कम से कम 10 और सीटों की आवश्यकता थी। ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने टीवीके का साथ दिया, और वीसीके व आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन से पार्टी राज्य की सत्ता तक पहुंच पाई। वहीं, इस फैसले को रणनीतिक आवश्यकता के रूप में भी देखा जा रहा है। पहली बात तो यह कि जिस गठबंधन के साथ टीवीके राज्य में सरकार चला रहा है, गठबंधन का ढांचा भी काफी हद तक वैसा ही है। दूसरा, यह कदम टीवीके को लोकसभा चुनाव 2029 में सीटों की मजबूत दावेदारी पेश करने का अवसर देगा, जिससे उसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए गठबंधन की तलाश या गठन से मुक्ति मिलेगी। शनिवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस, टीवीके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल के शीर्ष नेता शामिल हुए। टीवीके का प्रतिनिधित्व अधव अर्जुन और मारी विल्सन ने किया। टीवीके पहले मजबूती से सी जोसेफ विजय को प्रधानमंत्री पद के अगले चेहरे के तौर पर पेश कर रही थी, जिसके चलते कांग्रेस के साथ उसकी तीखी बयानबाजी भी हुई थी। अर्जुन ने कहा था, मैं आज साफ तौर पर कहता हूं कि प्रधानमंत्री दक्षिण से ही आना चाहिए और दक्षिण से ही प्रधानमंत्री बनेगा, हो सकता है अभी नहीं। भविष्य में वह हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करेगा और हर भारतीय के साथ समान व्यवहार करेगा। अब गठबंधन में शामिल होने के बाद विजय की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो सकती है।हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थीं कि द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम सांसद कनिमोई कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। इस संबंध में उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

नेक्स्टऐज मीडिया एंड कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसर्स साई प्रिंटिंग प्रेस डी- 85 सेक्टर-06 नोएडा 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा- 201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक: रिंकू यादव संपादक: अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 फोन : 0120-4403949, ईमेल unplugindia26@gmail.com